RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष 23 अंक 09 05 मई 2023

जगत विज़न

किसकी शह, किसकी मात...
किसे मिलेगा जनता का साथ

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
दिल्ली संवाददाता	नीरज दिवाकर
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
उत्तरप्रदेश संवाददाता	वेद कुमार मौर्य

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका **वर्ष 23 अंक 09 05 मई 2023**

(पृष्ठ क्र.-6)

■ कर्नाटक चुनाव के नतीजों का एमपी की राजनीति पर पड़ेगा असर ?.25

■ इतिहास के सबसे खराब निर्णयों के लिए जाना जायेगा वीडी शर्मा का कार्यकाल 26

■ चुनाव के पहले अशोक गहलोत सरकार ने खेला मास्टर स्ट्रोक.30

■ त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार 34

■ बिना सारथी के केजरीवाल ! 39

■ भारतीय पर्व-परम्पराओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग है गौ-वंश 42

■ प्रत्येक मतदाता को नमन 44

■ देश की सियासत में चमकते चेहरा बने योगी आदित्यनाथ 48

■ मनरेगा की जड़ें रामराज्य में हैं 52

■ जनसंख्या वृद्धि खुशी के साथ चिंता भी ! 56

■ पानी पर कब्जे का सवाल 60

■ Hunger and Food Distribution in India 62

ED के घर देर है; अंधेर नहीं!
मस्त रहो मस्ती में, आग लगन दो बस्ती में!
ED
विजया:)

बिगड़ते राजनेताओं के बोल और गर्म होती राजनीति

राजनीतिक दल एक–दूसरे पर आरोप –प्रत्यारोप लगाते रहते हैं , लेकिन चुनाव के दिनों में इसका स्तर निम्नतर हो जाता है। राजनेताओं के बिगड़ते बोलो ने राजनीति को गर्माने का अवसर देती हैं। हमने कई बार देखते हैं कि चुनावों के समय इस तरह के बोल देखने को मिलते हैं। सियासत के इस माहौल में इस तरह के बोल हमें कई मायनों में असमंजस में डालते हैं। कई बार राजनीतिक दलों को अपने नेताओं के बिगड़े बोलों के कारण चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ा है। एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक चुनाव के दौरान एक ऐसा ही बयान जारी कर दिया है, जिसको लेकर सियासत गरम है। जानकार यहां तक कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस को चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहरीले साँप की तरह हैं। इस पर भाजपा बिफर गई। भाजपा की ओर से तीखी प्रतियिाएं आईं और उसने कहा कि यह कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय मंत खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि इस खड़गे ने सफाई दी है और कहा है कि उनकी टिप्पणी भाजपा के विचारधारा के ख़िलाफ़ थी और यह व्यक्तिगत हमला नहीं था। राय में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कन्नड़ में कहा था, मोदी एक जहरीले सांप की तरह हैं। इस सांप को चाटने की कोशिश मत करो यह जांचने के लिए कि यह जहरीला है या नहीं। यदि आप इसे चखते हैं, तो आप मर चुके होते हैं। बाद में उन्होंने ट्वीट कर सफाई दी कि उनका मतलब था कि भाजपा सांप की तरह है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने यह भी कहा कि वह भाजपा की नफरत की राजनीति के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी या किसी अन्य व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला नहीं थी, बल्कि उनकी विचारधारा पर थी। भाजपा ने इसे ठीक उसी तरह चुनावी मुद्दा बना लिया है, जिस तरह गुजरात में चुनाव से पहले नीच शब्द को बनाया गया था। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने इसी मुद्दे पर कर्नाटक में खडके पर पलटवार किया। पूनिया ने कहा– पूरे कर्नाटक की जनता को मल्लिकार्जुन खड़गे ने चैलेंज किया है। कांग्रेस को जवाब देने की हिम्मत जनता और हमारे कार्यकर्ता रखते हैं। इधर, केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस की प्रवृत्ति मोदी को विभिन्न नामों से बुलाने की है। उन्होंने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस अपशब्द का इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी से खड़गे आते हैं, उसके नेता कभी मोदी को मौत का सौदागर, कभी दुर्योधन, कभी गटर का कीड़ा, कभी आम चायवाला कहते हैं। लोकतंत्र में इस तरह के शब्दों का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है।

विजया पाठक

किसकी शह, किसकी मात...
किसे मिलेगा जनता का साथ

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल बज चुका है। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। संगठन स्तर पर कसावट शुरू हो गई है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जिताऊ उम्मीदवारों की खोज परख भी प्रारंभ हो गई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अपने अंदरूनी सर्वे के आधार पर विधायकों के टिकट तय करने की रणनीति पर कार्य कर रही है वहीं कांग्रेस भी अब ऐसे प्रत्याशियों की खोज में लगी है जो अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर छबि रखते हों। दोनों प्रमुख पार्टियां 2023 के विधानसभा चुनाव में फूंक-फूंक कर कदम रखने वाली हैं क्योंकि हालात बता रहे हैं कि इस बार टक्कर 2018 जैसी ही होने वाली है। टांके की इस टक्कर में जिस भी पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में गलती नहीं करेगी वह पार्टी सत्ता पर काबिज हो जायेगी। सत्ता के इस संघर्ष में दोनों की प्रमुख पार्टियां पूरे दमखम के साथ तैयारियों में जुटी हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों ही चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। सत्तासीन बीजेपी सरकार को एंटी एंकम्बेंसी का डर सता रहा है और पिछली कमलनाथ सरकार के कामों से लोगों के मन में जो पिछली सरकार की छबि बनी है उससे डरी हुई है। कमलनाथ भी अपने 18 माह के कार्यो को लेकर चुनावी मैदान पर उतरे हैं। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है। यही कारण है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। दोनों ही दल एक-दूसरे पर हमलावर हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव ऐसा चुनाव था जिसमें कांग्रेस को डेढ़ दशक बाद न केवल बढ़त मिली थी बल्कि सत्ता भी हासिल हुई थी, वहीं भाजपा डेढ़ दशक तक सत्ता में रहने के बाद बहुत कम अंतर से कांग्रेस से पीछे रह गई थी। यह बात अलग है कि महज 15 माह बाद कांग्रेस में टूट हुई और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए, जिसके चलते भाजपा फिर सत्ता में लौट आई। पिछले चुनाव के नतीजों से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही सीख ली है। यही कारण है कि वे अगले चुनाव में किसी भी तरह की चूक को दोहराने को तैयार नहीं हैं। साथ ही उनकी कोशिश है कि जीत का अंतर इतना बड़ा हो कि सरकार बनाने में किसी भी तरह की बाधा न आए। पिछली बार कमलनाथ ने जो धोखा खाया है उससे सबक लेते हुए ही वह इस बार कोई गलती भी नहीं करने वाले हैं जिससे कांग्रेस को कोई नुकसान न हो पाये। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार बहुमत के आंकड़े 116 से आगे 150 का टारगेट लेकर चल रही है। बीजेपी ने मध्यप्रदेश में चुनाव से पहले लाडली बहना स्कीम लॉन्च कर दी गई। इसमें महिलाओं के खाते में 01 हजार रुपए डाले जाएंगे। इस तरह की स्कीम्स से पता चल रहा है कि पार्टी हड़बड़ाहट में है। प्रदेश में 07 दिसंबर 2023 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। राज्य में जहां एक तरफ बीजेपी पूरे जोर-शोर के साथ कार्यक्रमों और योजनाओं का ऐलान कर रही है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों पर विचार कर रही है। प्रदेश में मिली हुई सत्ता जाने के बाद इस बार कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए। पार्टी ने उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए भी फॉर्मूला बना दिया है। वहीं मौजूदा शिवराज सरकार कर्ज पर कर्ज लेकर चुनाव में जीत के लिए वृहद स्तर पर आयोजनों का झड़ी लगा रही है। सभी वर्गो को साधने में कर्ज लेकर पैसा पानी की तरह बहा रही है।

विजया पाठक

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल अब से कुछ माह में बजने को है। ऐसे में प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक पार्टियां भी अपनी चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। प्रदेश में सत्तारुढ़ शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि बीते एक वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह खुद पांच से छः बार मध्यप्रदेश का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लगातार दौरों ने प्रदेश की भाजपा और

मध्यप्रदेश में बीजेपी इस बार पूरी तरह से पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व पर निर्भर है। पार्टी के बड़े-बड़े नेता बीजेपी के प्रति माहौल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मध्यप्रदेश को देंगे। इसकी बानगी हम पिछले एक साल में देख चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और तमाम बड़े नेता लगातार मध्यप्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि इस बार प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो चुनाव में प्रदर्शित किया जा सके।

सत्ता, सगंठन पर सवालियां निशान खड़ा कर दिया है। भाजपा के शीर्ष नेताओं के लगातार हो रहे दौरों से इस बात का आंकलन भी लगाया जाने लगा है कि प्रदेश में भाजपा के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर प्रदेश भाजपा जनता से

पिछले कुछ समय से मध्यप्रदेश में कांग्रेस मजबूत स्थिति में हैं। खासकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस बेहतर स्थिति में आ गई है और कांग्रेस के प्रति माहौल बना है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार प्रदेश में सक्रिय होकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बूथ लेवल से लेकर उच्च स्तर तक कसावट ला रहे हैं। विभिन्न मामलों में मौजूदा सरकार को घेरते हुए कांग्रेस की उपलब्धियों को गिना रहे हैं।

वोट मांग सके। यही कारण है कि मोदी और अमित शाह लगातार प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं।

सात महीने में 05 दौरे कर चुके

मोदी- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगर बात करें तो मोदी खुद सात महीने में पांच बार

230 सदस्यों वाली मध्यप्रदेश विधानसभा में सत्ता का जादुई आंकड़ा 116 है। इस जादुई आंकड़े को पाने के लिए प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ऐड़ी–चोटी का जोर लगा रहीं है। सत्ता के इस खेल में किसकी शह होती है और किसी मात होगी इसका फैसला अगले कुछ महिनों बाद हो जायेगा। 2023 का यह विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कमलनाथ विरूद्ध कमल के बीच होने वाले इस मुकाबले में दोनों की साख दांव पर लगी हुई है।

मध्यप्रदेश का दौरा कर चुके हैं। मोदी के इस दौरे की शुरुआत सितंबर 2022 में कूनो पालपुर से हुई थी। इसके बाद महाकाल कॉरिडोर का शुभारंभ, वंदे मातरम् ट्रेन का शुभारंभ और हाल ही में रीवा में पंचायती राज दिवस का आयोजन। केंद्र सरकार के प्रमुख आयोजनों का मध्यप्रदेश में होना और उनमें शामिल होने मोदी का आना साफतौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश भाजपा की स्थिति को लेकर शीर्षस्थ नेता भी खतरा महसूस कर रहे हैं।

शाह ने भोपाल, छिंदवाड़ा किया एक-दूसरी तरफ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मोदी की राह पर चलते हुए निरंतर प्रदेश के अलग-अलग दौरे कर भाजपा के सत्ता और संगठन को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार मोदी की मप्र यात्रा की शुरुआत जबलपुर से हुई। जिसके बाद वे लगातार दो से तीन बार

बीजेपी पर भारी, कांग्रेस की तैयारी

इस चुनाव को लेकर गंभीर है और पूरी कमान प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ संभाले हुए हैं। वे खुद लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और जमीनी स्तर की रिपोर्ट भी तलब करने में लगे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी में जिस उम्मीदवार की जीतने की क्षमता ज्यादा होगी, उसे टिकट देने में प्राथमिकता दी जाएगी। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, उनका ध्यान रखा जाएगा और तीसरी सबसे अहम बात पार्टी के सर्वे में नाम होना है। आपको बता दें कि गुजरात में खराब प्रदर्शन के बाद भी हिमाचल की जीत से कांग्रेस उत्साहित है। यही वजह है कि पार्टी एमपी में भी सत्ता में आने की पूरी उम्मीद लगा रही है। इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है और पार्टी एक साल पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है। मध्यप्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में इस समय कांग्रेस के 96 विधायक हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी के पास 126 विधायक हैं। 04 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि दो बसपा और एक सपा का विधायक है। खबर है कि कांग्रेस इस बार एमपी में करीब 80 वर्तमान विधायकों को टिकट दे सकती है, जबकि 20 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। जिन सीटों पर पार्टी बहुत कम अंतर से हारी थी, वहां उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे। वहीं बीजेपी भी एमपी में चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अब देखना है कि कांग्रेस, बीजेपी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाती है। विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा है। सियासी दलों ने अभी से चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। तैयारी दोनों खेमे में चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मिशन 2023 की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। भोपाल में लगातार वह अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। साथ ही बीजेपी से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। कमलनाथ ने 2023 में पार्टी की जीत पक्की करने के लिए फार्मूला तैयार कर लिया है। इस बार जोर उन सीटों पर ज्यादा है, जहां कांग्रेस लगातार हार रही है। 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने प्रदेश में कुछ ऐसे सीटों की पहचान की है, जहां पार्टी लगातार हार रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने ऐसी 70 सीटें चिह्नित की है, जहां वह जीत के लिए तरस रही है। इन सीटों पर वर्षो से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में पार्टी को मानना है कि अगर इन सीटों पर जीत हासिल करनी है तो वहां से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के पास मौका होना चाहिए। वहीं, कांग्रेस की विशेष नजर उन सीटों पर जहां से बीजेपी के लोग सात से आठ बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं।

भोपाल पहुंचे और हाल ही में वे छिंदवाड़ा के दौरे पर पहुंचे। छिंदवाड़ा में देखा गया कि अमित शाह की रैली को सफल बनाने के लिए शिवराज सरकार के आला मंत्रियों को भी ऐड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। क्योंकि कमलनाथ के किले को भेदने के जिस

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मध्यप्रदेश कांग्रेस में जान फूंक दी है। पार्टी एकजुट होकर मौजूदा शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस नये अवतार में दिख रही है। पार्टी के तमाम नेता विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। पार्टी की तैयारियों को देखकर कहा जा सकता है कि टक्कर बहुत कड़ी होने वाली है।

कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने सीखा कदम से कदम मिलाकर चलने का हुनर

उद्देश्य के साथ शाह वहां पहुंचे थे वे वहां पूरी तरह से इस काम को करने में असफल रहे।

जितनी रैलियां उतना खर्चा, परिणाम जीरो- अगर हम मोदी और शाह की रैलियों पर नजर डाले और इनके आवभगत में होने वाले खर्चो पर नजर डाले तो शायद हम इस बात का आंकलन भी नहीं कर पायेंगे कि प्रदेश सरकार ने इनके आवभगत में कितना करोड़ रुपये फूंक दिया। सूत्रों के अनुसार एक-एक आयोजन में प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ से अधिक की राशि को खर्च किया। जबकि देखा जाये कि इतने आयोजन में खर्च हुए बजट से अगर सरकार चाहती तो जनता के हितों में कई प्रमुख फैसले करती जिसका फायदा जनता को मिलता। लेकिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह का काम करना बिल्कुल उचित नहीं समझा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सच में इन रैलियों का कोई फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा या फिर यह महज एक दिखावा बनकर रह जायेगा जिसके खर्च का भुगतान प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा।

क्या मोदी और शाह के चेहरे पर जीतेगी भाजपा?- मोदी और शाह के लगातार मप्र के दौरों को लेकर सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या इस बार भाजपा मोदी और शाह के

बीजेपी हाईकमान के भरोसे मध्यप्रदेश का भविष्य

चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। क्या प्रदेश में ऐसा कोई जनप्रिय और लोकप्रिय नेता नहीं है जिसके चेहरे पर प्रदेश में भाजपा सत्ता पर कायम रह सके। अब देखने वाली बात यह है कि क्या शाह और मोदी के दौरों का परिणाम प्रदेश भाजपा को मिलेगा या फिर एक बार फिर मोदी और शाह को यहां से निराश होकर जाना होगा।

विंध्य, महाकौशल पर यादा फोकस- सूत्रों के अनुसार इस बार शीर्षस्थ नेता इस बात को लेकर भी संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि प्रदेश में भाजपा एक बार फिर सत्ता कायम करने में सफल होगी। यही कारण है कि मोदी, शाह सहित प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी विगत कई महीनों से विंध्य, महाकौशल पर अधिक फोकस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि विंध्य, महाकौशल दो ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भाजपा को कमजोर बताया जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश संगठन इन क्षेत्रों पर अधिक फोकस कर रहा है।

बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल इस विधानसभा चुनाव में अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने लिए सत्ता तक का रास्ता चुन रही है और विकास यात्रा के साथ अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है, वहीं राहुल गांधी की सफल भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस भी विधानसभा 2023 के लिए कमर कस चुकी है। इसी के

मध्यप्रदेश बीजेपी का चेहरा भले ही शिवराज सिंह चौहान हैं, लेकिन इस बार बीजेपी हाईकमान ने शिवराज पर भरोसा कम दर्शाया है। ऐसे कई मौके आए है जब शिवराज की अपेक्षा पार्टी हाईकमान महत्वपूर्ण भूमिका में रहा हो। पिछले कुछ महिनों में पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं की प्रदेश में मौजूदगी यही दर्शाती है कि 2023 का चुनाव कॉंग्रेस विरूद्ध बीजेपी हाईकमान होने वाला है।

क्या भाजपा को भाजपा ही चुनौती देगी?

भाजपा के अंदरूनी सर्वे से खींची चिंता की लकीरें

भाजपा आलाकमान की नजर मध्यप्रदेश पर टिक गई है। यहां सत्ता बचाए रखने के साथ बड़े अंतर से जीत को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। आंकड़ों और संभावनाएं टटोलने के साथ प्रदेश नेतृत्व की तैयारियों को भी जांचने-परखने पर काम शुरू हो चुका है। पार्टी नेतृत्व ने मध्यप्रदेश में सत्ता-संगठन से वर्ष 2023 के विस चुनाव में जीत के लिए तैयार प्लान की जानकारी मांगी है। दरअसल पार्टी नेतृत्व भी मान रहा है कि भाजपा के लिए मिशन 2023 आसान नहीं है। मध्यप्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की सीटों में सबसे कम अंतर है। तमाम दल-बदल के बाद भी सदन में भाजपा के पास 127 और कांग्रेस के पास 96 विधायक हैं। 2018 के विस चुनाव में भी वोट शेयर देखें तो भाजपा को 41.6 प्रतिशत और कांग्रेस को 41.5 प्रतिशत वोट मिले थे। हालांकि 2020 में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा के वोट शेयर में खासी बढ़ोतरी देखी गई थी। लेकिन मध्यप्रदेश में सियासी नब्ज टटोलते हुए भाजपा आलाकमान की नजर सत्ता विरोधी रुझान के साथ पार्टी के सामने कई अन्य चुनौतियां पर पड़ रही है। ऐसे में नेतृत्व पहले राज्य स्तर के नेताओं से उनकी कार्ययोजना जानना चाहता है कि आखिर वे किस रणनीति के तहत सरकार में बने रहने का दावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में भाजपा मध्यप्रदेश में बहुमत पाने में सफल नहीं रही थी, लेकिन 2020 में कांग्रेस विधायकों द्वारा इस्तीफे देने के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन पाई थी। ऐसे में उपचुनाव की सीटों पर भाजपा को अपने पुराने चेहरों को घर बिठाना पड़ा था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए समर्थकों

साथ दोनों पार्टियां अपने अपने चुनावी मुद्दों के चयन में भी काफी सतर्कता बरत रही हैं। जाहिर है, चुनाव आते ही कुछ मुद्दे जैसे बेरोज़गारी, महंगाई, किसान और महिला सशक्तिकरण, खुद-ब-खुद ट्रेंड में आ जाते हैं। 2018 में कांग्रेस ने किसान और कर्ज़

को मौका देना पड़ा। फिलहाल सत्ता के समीकरणों के लिए सिंधिया समर्थकों को तवज्जो दिया जाता रहा, लेकिन अब 2023 के लिए पार्टी के पुराने चेहरे इन सीटों पर अपनी वापसी चाहते हैं। ऐसे में संगठन के सामने असंतोष का जोखिम हो सकता है। आलाकमान इस स्थिति से निपटने के उपायों पर सत्ता व संगठन की तैयारी जानना चाहता है। पार्टी चाहती है कि प्रदेश नेतृत्व अपना पूरा रोडमैप बताए कि वर्ष 2018 की परिस्थितियां और मौजूदा दौर में क्या अंतर आया है? आने वाले चुनाव में क्या चुनौतियां हैं, उनसे पार्टी कैसे निपटेगी? तब कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था, साथ ही कई मंत्रियों की सीट बेहद कांटेदार मुकाबले में बच सकी थी। कांग्रेस भले ही बहुमत के आंकड़े 116 तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन भाजपा से आगे पहुंचने में सफल हो गई थी। क्या प्रदेश की भाजपा सरकार को लेकर एक बार फिर जनता के मन में ऐसी धारणा बन रही है? इस पर सत्ता-संगठन की तैयारी की जानकारी भी आलाकमान को चाहिए। नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ। ग्वालियर महापौर की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। इन परिणामों ने स्पष्ट संकेत दिए कि इस क्षेत्र में भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। जिन क्षेत्रों में बेहतर परिणाम मिले हैं, वहां भाजपा की लहर बनाए रखने के साथ उन क्षेत्रों में वापसी की चुनौती बढ़ गई है, जहां कमल नहीं खिल सका है। इन परिणामों के परिप्रेक्ष्य में आलाकमान ने तैयारियों के संबंध में जानकारी भी प्रदेश से मांगी गई है। पिछले चुनाव में 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 109 सदस्य पहुंचे थे। यही कारण है कि भाजपा फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रही है। पार्टी ने अंदरूनी तौर पर जो सर्वे कराया है उसमें 40 से ज्यादा विधायकों की रिपोर्ट नकारात्मक आई है, तो वहीं पार्टी पदाधिकारियों और मंत्रियों की बैठक में आगामी रणनीति भी तय की गई है, जिसके मुताबिक प्रभारी मंत्रियों और संगठन से जुड़े लोगों को जिले स्तर पर तैनात किए जाने का फैसला हुआ है। नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ। ग्वालियर महापौर की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। इन परिणामों ने स्पष्ट संकेत दिए कि इस क्षेत्र में भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए एकतरफा नहीं रहने वाले। यह ऐसा चुनाव होगा जिसमें कार्यकर्ता और संगठन की भूमिका पिछले चुनावों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जिस भी दल ने बेहतर उम्मीदवारों का चयन किया और कार्यकर्ताओं की क्षमताओं का इस्तेमाल किया, उसके लिए सत्ता की राह आसान जरूर नजर आती है।

माफी के नाम पर ही मध्यप्रदेश में मतदाताओं को आकर्षित करने में सफलता हासिल की थी। इसलिए अब भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस इस बार भी इन्ही मुद्दों को थामे रखना चाहेगी, हालांकि उम्मीद है इन चुनावों में कांग्रेस, रोजगार के

क्या बीजेपी बदल सकती है सीएम चेहरा?

ऐसी चर्चा जोरों पर है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए एक नया चेहरा चुन सकती है, जैसा कि उसने गुजरात में कर चुनाव जीता। सीएम शिवराज चौहान को बदलने से पार्टी को संभावित सत्ता विरोधी लहर पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। एक खेमे का मानना है कि बीजेपी चुनावी लाभ के लिए बदलाव करेगी। दूसरे खेमे का कहना है कि कैबिनेट में फेरबदल तो होगा, लेकिन सीएम चौहान ही बने रहेंगे। मई में विपक्षी कांग्रेस ने कथित तौर पर न केवल राज्य स्तर के लिए, बल्कि स्थानीय मुद्दों और मांगों के आधार पर प्रत्येक जिले के लिए वचन पत्र (चुनाव घोषणा पत्र) तैयार करने का फैसला किया। यह एक गेम–चेंजिंग प्रयास हो सकता है। हालांकि जुलाई में भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल की। 30 फीसदी सीटों पर भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है जबकि 30 फीसदी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है। बाकी 49 फीसदी सीटों पर कांटे की टक्कर दिख सकती है। ऐसे में भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में कमल खिलाना पहले जैसा आसान नहीं है। भाजपा के सामने बड़ा एंटी इनकंबेंसी फैक्टर है। बताया जाता है कि भाजपा के अंदरखाने यह चर्चा चल रही है कि राज्य में पार्टी का नया चेहरा कौन होगा? बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में भाजपा मुख्यमंत्री का अपना फेस बदल सकती है। मध्यप्रदेश में पार्टी के सर्वे से पता चला है कि सीटें 80 से कम ही रहेंगी और इतने में सरकार नहीं बन सकती। मध्यप्रदेश में 2003 से लगातार भाजपा की सरकार है। बीच में 2018 में 15 महीने के लिए कांग्रेस को सत्ता मिली थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने लेकिन जल्द ही सियासी खेल हो गया। करीब 17 साल से शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 को चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। 30 नवंबर 2005 से 17 दिसंबर 2018 तक लगातार 13 साल 17 दिन तक वे मुख्यमंत्री रहे। फिर करीब डेढ़ साल कांग्रेस की सरकार रही और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। 23 मार्च 2020 से एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवराज के पास आ गई। उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए करीब 16 साल हो चुके हैं।

लिए तड़प रहे युवाओं के साथ, बेरोजगारी के मुद्दे को जमकर भुनाएगी। भाजपा की बात करें तो मध्यप्रदेश में पार्टी हर सर्वे में जीत से दूर नज़र आ रही है। इसकी एक वजह एंटी इनकम्बेंसी को भी माना जा सकता है। इतने सालों तक सत्ता में बने

क्या आप बिगाड़ सकती है सियासी गणित?

मध्यप्रदेश में आम आदमी पार्टी की चर्चा शुरू हो गई हैं। यहां पर आप को तीसरी पार्टी के रूप में देखा जाने लगा है। आप प्रदेश में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या आप प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का सियासी गणित बिगाड़ सकती है। वैसे आप ने प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। मप्र में पहली बार आम आदमी पार्टी का मेयर बना है। सिंगरौली में आप प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने भाजपा के उम्मीदवार को हराया। रानी भाजपा की नेता रह चुकी हैं। हालांकि ओवर ऑल आंकडों को देखते हैं तो यहां भी आम आदमी पार्टी ने करीब 60 से ज्यादा वार्डो में कांग्रेस का खेल बिगाड़ा। बुरहानपुर, खंडवा और उज्जैन में मेयर सीट पर भाजपा की जीत हुई। इन तीनों सीटों पर भी आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम की वजह से कांग्रेस की हार हुई। बुरहानपुर में एआईएमआईएम प्रत्याशी को 10 हजार से ज्यादा वोट मिले। इसी तरह उज्जैन में भाजपा उम्मीदवार केवल 736 वोटों से जीती। अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस-भाजपा की लड़ाई हो वहीं आप की एंट्री होती है। आमतौर पर कई राज्यों में कांग्रेस को आसानी से मुस्लिम वोटर्स का साथ मिल जाता है। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल इसी को तोड़ने में जुटे हैं। जहां-जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है, वहां आम आदमी गढ़ी की एंट्री होती है। अब केजरीवाल 2023 के मप्र के चुनाव में दल-बल के साथ उत्तर चुके हैं। गत दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भोपाल में आयोजित एक रैली चुनावी बिगुल फूंकते हुए घोषणा की कि पंजाब की तर्ज पर ही मप्र में अगर उनकी सरकार आई तो बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं का मुफ्त कर दिया जाएगा। प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने खुद का तेजी से विस्तार करना शुरू किया।

रहने के बावजूद कुछ मुद्दों पर बीजेपी अब भी कमज़ोर ही बनी हुई है। प्रदेश में जारी बीजेपी की विकास यात्रा का, खासकर ग्रामीण इलाकों में बहिष्कार इस बात का सबूत है कि मौजूदा सरकार से वो मतदाता खफा है जो असल में पोलिंग बूथ तक वोट

राजनीति का केंद्र बना आदिवासी समाज

मध्यप्रदेश की सियासत में इन दिनों समाज का सबसे पिछड़ा तबका यानी आदिवासी राजनीतिक दलों की जुबान पर है। प्रदेश की करीब 02 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी को लुभाने के लिए सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के नेता जोर लगा रहे हैं। पिछले चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिली, तो 15 साल बाद बीजेपी को सत्ता से दूर होना पड़ा। पिछले चुनाव में हुई चूक को भाजपा दोहराना नहीं चाहती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए पेसा कानून लागू किया है। आदिवासियों से जुड़ी तमाम योजनाओं, जनजातीय जननायकों की प्रतिमाएं लगवाने और स्मारकों का विकास कराने जैसे काम तेजी से शुरू किए हैं। 15 नवंबर से मप्र में पेसा कानून प्रभावी होने के बाद सीएम खुद आदिवासी क्षेत्रों में जाकर पेसा जागरूकता शिविर लगाकर आदिवासियों से सीधे जुड़े। मप्र के 20 जिलों के 89 ब्लॉक आदिवासी बहुल हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंदौर संभाग के 40 विकासखंड आदिवासी बहुल हैं। इसी वजह से लगातार हो रहे इन राजनीतिक कार्यक्रमों का केंद्र इंदौर ही है। दूसरे नंबर पर जबलपुर संभाग के 27 ब्लॉक जनजातीय बहुल हैं। विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो साल भर तक आदिवासी राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र इंदौर ही रहा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इसी आदिवासी बाहुल्य इलाके में अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं। मध्यप्रदेश के 20 जिलों में कुल 89 विकासखंड आदिवासी क्षेत्रों में हैं। प्रदेश की लगभग 84

देने पहुंचता है। शायद इसीलिए शिवराज सरकार साहित्य कला से लेकर महिला और युवाओं को आर्थिक लाभ लेकर लुभाने में जुटी है। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस या अन्य सभी दलों का, बीजेपी को घेरने के लिए इस बार

सीटों पर आदिवासी वोटर ही तय करते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। मध्यप्रदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट भी आदिवासी बहुल इलाकों का रखा गया था।

50 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी आबादी वाले सबसे यादा गांव मध्यप्रदेश में- केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा जनजातीय आबादी वाले कुल 36,428 गांव हैं। आधी से ज्यादा आदिवासी आबादी वाले गांवों में मप्र देश में पहले नंबर पर है। एमपी के 7307 गांवों में आदिवासियों की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर राजस्थान में 4302 गांवों में 50 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 4029, झारखंड में 3891, गुजरात में 3764, महाराष्ट्र में 3605 गांवों में आधे से ज्यादा आदिवासी रहते हैं। मप्र विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं इनमें से 47 आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। साथ ही आदिवासियों की बड़ी आबादी होने से प्रदेश की 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। प्रदेश में 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित इन 47 सीटों में से भाजपा ने 31 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 15 सीटें आई थीं, लेकिन 2018 के चुनाव में भाजपा को इसी ट्राइबल बेल्ट से करारी हार मिली और वो सिर्फ 16 पर ही जीत दर्ज कर सकी। कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थीं और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं आदिवासी वोटों के कारण ही 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी।

शिवराज सरकार ने पेसा एक्ट लागू कर खेला बड़ा दांव- शिवराज सरकार ने 15 नवंबर प्रदेश में पेसा एक्ट (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स) लागू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहडोल से इसकी शुरुआत की थी। एमपी में पेसा कानून लागू होने के बाद से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद आदिवासी बाहुल्य जिलों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया।

सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही होगा। बेरोज़गारी के बढ़ते ग्राफ को हथियार बनाकर राजनैतिक दल सत्ता की रेस में आगे निकलना चाहते हैं। यही एक मुद्दा है जिसे बीजेपी अपना हथियार नहीं बना पा रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि अब

विदिशा जिले के बरोदियां और आसपास के गांवों की बदतर स्थिति

रोजगार न मिलने से पलायन को मजबूर ग्रामीण

राजधानी भोपाल से सटे विदिशा जिले के बंजारा समुदाय बाहुल्य चार गांवों की दयनीय स्थिति मध्यप्रदेश की दूसरी ही तस्वीर बयां कर रही है। प्रदेश की वर्तमान सरकार भले ही राय के विकास और बदलती तस्वीर के गुणगान कर रही हो लेकिन इन गांवों को देखकर लगता है कि विकास के झूठे आंकड़ों से प्रदेश को महिमामंडित किया जा रहा है। गौरतलब है कि विदिशा जिले में करीब 10 वर्ष पहले संजय सागर बांध का निर्माण किया गया था। यह बांध विदिशा जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर के शमशाबाद विकासखंड अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत बरोदिया और चौड़ियाई, अलनिया, तलैया और इमलापुरा के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। बांध बनने से खेती का अधिकतर हिस्सा डूब में आने के कारण मुआवजा भी नहीं मिल सका, क्योंकि उस जमीन का इनके पास पट्टा भी नहीं था। इन गांवों के रहवासी अब नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत बरोदिया के ये गांव और 400 परिवार आज भी संजय सागर बांध के डूब क्षेत्र में बसे हुए हैं। आज भी इन गांवों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जगत विजन की टीम ने जब इन गांवों की स्थिति को देखा तो हकीकत जानकर बड़ी हैरानी हुई। अधिकतर गांवों के घरों में ताले पड़े मिले और जिन घरों में ताले नहीं थे उन घरों में केवल बुजुर्ग ही थे। हमने जब इन लोगों से बात की तो इनका कहना था कि शासन-प्रशासन स्तर पर हमारे लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। रोजगार से लेकर आजीविका के लिए दर-दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं हमारे बच्चे रोजगार के लिए देश के अन्य रायों में जाने को मजबूर हैं।

कांग्रेस सत्ता में आने के लिए किसानों को अपनी सीढ़ी बनाने के बजाय, ऐसा मुद्दा तलाशना चाहेगी जिसका बीजेपी के पास कोई तोड़ न हो। विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी के लिए जीत का मुद्दा पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी समाज

खोखले हैं सरकार के सारे दावे और वादे

प्रदेश की मौजूदा शिवराज सरकार आज भले ही सार्वजनिक मंचों से कहते हुए थक नहीं रहे हैं कि मध्यप्रदेश आज विकास के कई कीर्तिमान रच रहा है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। निवेश आने से लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। लेकिन इन इन कुछ गांवों की तस्वीर देख कर तो यही लगता है कि सरकार के सारे दावे और वादे सभी खोखले हैं। सिर्फ मंचों से भाषण देने से और झूठे दावे करने से लोगों की समस्याएं हल नहीं होगी। सरकार को सबसे पहले लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना होगा। उन्हें रोजगार के अवसर देने होंगे। बरोदिया जैसे केवल गांव नहीं है। प्रदेश में और भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को रोजगार न होने की स्थिति में पलायन करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि लोगों की कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए सरकार प्रतिमाह हजारों करोड़ रूपये कर्ज पर ले रही है। अब सवाल उठता है कि जब यह कर्ज लोगों के कल्याण में ही काम नहीं आ रहा है तो ऐसे कर्ज लेने की क्या जरूरत है? बेहतर होता कि सरकार कर्ज लेकर जरूरतमंद लोगों के लिए खर्च करती।

प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को नहीं सुध लेने की फुरसत

विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग हैं। विश्वास सारंग कहने को तो वह इस जिले के मंत्री हैं लेकिन उन्हें अपने जिले में जाने की फुरसत ही नहीं है। कभी कभार जाते भी हैं तो केवल किसी कार्यम में मुख्य अतिथि के रूप में या किसी कार्यम का फीता काटने जाते हैं। जबकि यह जिला उनके निवास से कुछ ही दूरी पर है। सारंग को पता ही नहीं है कि उनके जिले में क्या हो रहा है? उनके प्रभार के जिले के लोगों की क्या समस्यायें हैं? रोजगार के क्या अवसर हैं? और जो हैं उनकी क्या स्थिति है? ऐसे किसी भी मामले से मंत्री जी को कुछ लेना देना नहीं है। जिले के लोगों की भी यही शिकायत हैं। कुछ ऐसी ही शिकायत इन गांव वालों के लोगों की भी हैं। लोगों का कहना है कि हमने कई बार प्रभारी मंत्री से इस संबंध में बात करने की कोशिश की है। लेकिन आज तक हमारी परेशानी पर कोई काम ही नहीं किया है।

बंजारा बाहुल्य हैं गांव

यह सभी गांव बंजारा समुदाय बाहुल्य गांव हैं। इन गांवों के जनप्रतिनिधि भी यादातर बंजारा हैं। ये लोग खेती की जमीन बांध के निर्माण में डूब जाने से इनका रोजगार भी छिन गया है। अब केवल मेहनत मजदूरी से ही अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। बरोदिया पंचायत की सरपंच गुड्डी बाई भी बंजारा हैं। वे बताती हैं कि उनकी पंचायत में समाज के डेढ़ सौ में से करीब सौ परिवार के युवा रोजगार के लिए पलायन कर गए हैं। इनका मानना है कि जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा तो वह कहीं न कहीं तो रोजगार की तलाश में जायेंगे।

रोजगार के लिए छोड़ा घर-परिवार

केंद्र से लेकर राय सरकारें तक गांवों में ग्रामीणों को साल भर रोजगार उपलब्ध कराने के दावे करती हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ अलग है। इन चार गांवों के 150 में से लगभग 100 घरों में ताले लटके हुए हैं, क्योंकि इन घरों के लोग रोजगार के लिए आंध्रप्रदेश और राजस्थान के शहरों में चले गए हैं। जिन घरों में ताले नहीं लगे वहां भी सिर्फ बुजुर्ग ही घरों की रखवाली करते मिलते हैं। गांव चौड़ियाई में बंजारा समाज के 50 घर हैं, लेकिन 25 से अधिक घरों में कोई नहीं रहता। यह स्थिति अन्य तीन गांवों की भी है। बरोदिया गांव के अजय सिंह का कहना है कि जिले में मजदूरी मिलती नहीं है। इसलिए वे दूसरे रायों में जाकर फुटपाथ पर सामान बेचने का काम करते हैं। कुछ लोग भवन निर्माण में मजदूरी भी करते हैं। कुछ लोगों ने पथ-विक्रेता योजना में आवेदन जमा किये थे लेकिन बैंक दस हजार रुपये का कर्ज देने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में पलायन करना ही एकमात्र रास्ता है।

हो सकते हैं वहीं, कांग्रेस का मुख्य दांव केवल बेरोज़गारी के रास्ते युवाओं पर ही सधा होगा। और इस बार बीजेपी को घेरने के लिए और सत्ता तक अपना रास्ता बनाने के लिए कांग्रेस इस एक मुद्दे को अपना चुनावी मुद्दा बनाएगी।

जो उन्हें जीत की सीढ़ी तक ले जाने का काम करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की हालत इस समय तो कमजोर ही लग रही है। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की कोशिश होगी कि वे 2024 से पहले भाजपा को हराने का संदेश दे सकें। आज के समय में विपक्ष में एकजुटता की कमी दिखने के बावजूद भाजपा के लिए उत्साहजनक वातावरण नहीं बना हैं।

प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनाव जीतने का दावा कर रही हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियों को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भाजपा में समन्वय का अभाव है। इसका खुलासा खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल प्रवास के दौरान किया था। इसके साथ ही प्रदेश में नवंबर-दिसंबर 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले सीटों और प्रत्याशियों को लेकर किए जा रहे पार्टियों के अंदरूनी सर्वे बाहर आने लगे हैं। इसी के हवाले से राजनीतिक दलों के जिम्मेदार बयानबाजी भी कर रहे हैं। कांग्रेस-भाजपा दोनों ही पार्टियों ने जीतने वाले उम्मीदवारों पर ही दांव लगाने का निर्णय लिया है। दोनों पार्टियों के ऐसे उम्मीदवारों की टिकट पर खतरा मंडरा रहा है, जो वर्तमान में विधायक हैं परंतु उनका प्रदर्शन खराब है। दोनों पार्टियों के प्रभारी नेताओं ने पिछले दौरे में इस बात के स्वयं के बजाय पहले पार्टी को प्राथमिकता में रखें। विधायक हो या बड़े नेता सभी को पार्टी की बात माननी होगी। टिकट वितरण में नये चेहरों को जगह मिल सकती हैं। मप्र में भाजपा ने 200 विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस मिशन की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी है। लेकिन प्रदेश में निकाली गई विकास यात्रा ने मंत्रियों की सक्रियता और परफॉर्मेंस की पोल खोलकर रख दी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश के अधिकांश मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा की

मध्यप्रदेश में कांग्रेस की वापसी के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं में एक और नेता का नाम उभरा है, वह नेता है जीतू पटवारी। जीतू पटवारी ने पिछले कुछ महिनों में विभिन्न मामलों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सड़क से लेकर सदन तक में सरकार से सवाल जवाब किया है। आंकड़ों से पटवारी ने सरकार को जमकर घेरा है। यही वजह से पटवारी हमेशा लाईम लाईट में रहते हैं।

स्थिति कमजोर हो रही है। विकास यात्रा के दौरान मंत्रियों के क्षेत्र में ही सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं। खासकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों की शिकायत की हैं। संघ और संगठन के पास पहुंची शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आनन-फानन में बैठक बुलाकर मंत्रियों को फीडबैक दिया और हिदायत दी है कि एक माह के अंदर अपनी स्थिति माननी होगी टिकट वितरण में नए मजबूत कर लें, वरना गाज गिरनी तय है। संघ और संगठन को मिले फीडबैक के अनुसार अधिकतर मंत्रियों के खिलाफ शिकायत यह है कि उन्होंने प्रभार वाले जिलों को उपेक्षित छोड़ दिया है और अपने जिले में केवल अपनों को महत्व दे रहे हैं।

अरूण यादव मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग का प्रमुख चेहरा है। उभरते इस चेहरे से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव 2023 में काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि अरूण यादव अपने क्षेत्र के साथ-साथ प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी काफी प्रभाव रखते हैं। वर्तमान में अरूण यादव को चुनाव को देखते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है।

गौरतलब है कि 15वीं विधानसभा का दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। साल के अंत में रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने तेज कर दी हैं। दोनों ही प्रमुख दलों के नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप और वादों का सिलसिला भी दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कोई भी पार्टी आंकड़ा (116) नहीं छू पायी थी। कांग्रेस को 01 करोड़ 55 लाख 95 हजार 153 मत प्राप्त हुए थे। कुल मतों का प्रतिशत 40.9 रहा। कांग्रेस ने 229 सीटों पर लड़ा था। 114 सीटों पर प्रत्याशियों को जीत मिली। वहीं भाजपा को 01 करोड़ 65 लाख 42 हजार 980 मत प्राप्त हुए थे। बीजेपी को कांग्रेस से एक प्रतिशत अधिक मत प्राप्त हुए। कुल मतों का प्रतिशत 41 रहा। भाजपा ने प्रदेश की सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। चुनाव में भाजपा के टिकट पर 109 विधायक बने। इस तरह भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए भाजपा लगातार रणनीति बनाकर काम कर रही है। वहीं पार्टी के रणनीतिकार वर्तमान विधायकों को स्थिति का आंकलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा केंद्रीय नेतृत्व और संघ लगातार मंथन और समीक्षा में जुटे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी में लगभग 40 प्रतिशत चेहरे बदले जा सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 60 प्रतिशत विधायकों को ही टिकट मिलेगा, बाकी सभी नए चेहरे होंगे। जिन चेहरों पर दांव लगाया जा रहा है वह जीतने वाले ही होंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 150 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सभी तरह के प्रयोग किये जा सकते हैं। यह बात भी सामने आ रही है कि कमजोर प्रदर्शन करने वाले लगभग 35 प्रतिशत विधायकों का टिकट खतरे में है। कांग्रेस ने जिन विधायकों के प्रदर्शन की बात की है उनमें से ज्यादातर नये विधायक हैं। कांग्रेस अपने लक्ष्य को पाने के लिए 230 में से कांग्रेस उन 70 सीटों पर फोकस करेगी, जहां पार्टी को लंबे समय से हार का सामना करना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इस बार कई सीटों पर 06 महीने पहले ही कैंडिडेट घोषित करने वाली है। प्रत्याशी को लंबा वक्त मिला तो वह अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब हो सकता है। एक बात यह भी निकलकर आई है कि जहां भाजपा मजबूत स्थिति में है, वहां बड़े नेताओं की जगह उनके बेटों को उतारा जाएं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा- हमारा फोकस पिछले दो चुनाव में हारी सीटों पर जीत तय करना है। इससे पहले कमलनाथ ने अप्रैल-मई 22 में एक सर्वे कराया था। अब तक कमलनाथ तीन सर्वे करा चुके हैं। इसमें विधायकों के कामकाज का मूल्यांकन किया गया था। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर विधायक ने कितनी आवाज उठाई। जनता को कितना वक्त दिया। सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव रहे। दूसरे सर्वे में विधायक की लोकप्रियता की जमीनी हकीकत देखी गई। यानी क्षेत्र की जनता उन्हें आगे भी अपना प्रतिनिधि बनाए रखना चाहती है या

मप्र में 170 सीटों पर किसानों का असर

प्रदेश की 80 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों से आती है। प्रदेश की राजनीति में किसानों का वर्चस्व है। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते यहां की राजनीति भी कृषि के इर्दगिर्द घूमती रहती है। चुनावों के समय भी किसानों को लेकर तरह तरह के लोकलुभावन वादे किये जाते हैं। बताया जाता है कि 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किये जाने के वादे के कारण जीता था। वहीं बीजेपी भी किसानों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ओलावृष्टि हुई। इसके बाद शिवराज सरकार सर्वे और मुआवजा को लेकर जमीन पर उतर आयी। मप्र में 230 विधानसभा सीटों में से 170 सीटें ऐसी हैं, जहां किसान वोट निर्णायक भूमिका में हैं। 20 जिलों की 51 तहसीलों में और बेमौसम की बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में कांग्रेस पाटी अब बारिश और ओलावृष्टि के जरिए किसानों के बीच पहुंचने की तैयारी में है तो वहीं भाजपा सरकार जल्द से जल्द सर्वे पूरा कर किसानों को राहत राशि वितरण कर किसान हितैषी बताने की तैयारी में है। मतलब साफ है विधानसभा चुनाव से पहले जो दल किसानों का भरोसा जीतने में सफल होगा सत्ता की चाबी उसी पार्टी के हाथ में होगी।

नहीं ? यदि हां तो क्या वजह है और नहीं तो क्या कारण हैं। दूसरे सर्वे में पहले सर्वे के बाद विधायकों की स्थिति में बदलाव का आंकलन भी किया गया है।

राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने शिवराज सरकार को कई मुददों पर घेरा है। वह चाहे कानून व्यवस्था की बात रही हो या बेराजगारी की बात रही हो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सरकार को कटघरें में खड़ा किया है। इसके साथ ही चुनावी नफा-नुकसान को साधने में एक तरफ जहां बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी तो कांग्रेस भी बीजेपी से पीछे नहीं रही। खासकर आदिवासी कार्ड बीजेपी ने पूरे साल खेला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों से जुड़ा कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां बीजेपी ने दस्तक न दी हो। बिरसा मुंडा से लेकर टंटया मामा भील तक से लेकर आदिवासियों को खूब भुनाने की कोशिशें हुईं। इसके अलावा राजनीतिक रूप से और भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने प्रदेश को हमेशा चर्चा में रखा। पंचायत चुनाव से लेकर नगरीय निकाय चुनाव में राजनीति गरमाती रही। कहा जा सकता है कि पूरे वर्ष सरकार और कांग्रेस हमेशा आमने सामने रहे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 2023 विधानसभा चुनाव की बिसात 2022 के प्रारंभ से ही बिछना शुरू हो गई थी।

कर्नाटक चुनाव के नतीजों का एमपी की राजनीति पर पड़ेगा असर?

राजेन्द्र कानूनगो

दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। दोनों ओर से बयानों के तीर चल रहे हैं। यू टर्न लिए जा रहे हैं। यहां अगले महीने 10 मई को मतदान कराया जाएगा। 13 मई को चुनाव परिणाम जारी किया जाएगा। इससे पहले कई चैनलों की ओर से ओपनियन पोल किए गए हैं कि यहां पर अगली सरकार किसकी बनेगी? कर्नाटक चुनाव के मतदान से पहले किए गए एक सर्वे में हजारों लोगों से राज्य मांगी गई, जिसके आधार पर, यह निष्कर्ष निकला कि कौन-सी पार्टी यहां सरकार बना सकती है। सर्वे के मुताबिक पूरे विधानसभा चुनाव में कर्नाटक राज्य से इस बार बीजेपी 80 से 90 सीटें ला सकती है। हालांकि, कांग्रेस उससे यादा सीटें लाने की स्थिति में है। उसे यहां पर 105 से 115 सीटें मिल सकती हैं। वहीं, क्षेत्रीय दल जेडीएस को राज्य में 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। बहुमत के लिए किसी भी दल को कुल 224 में से 113 सीटें चाहिए होंगी। अभी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। जैसा कि पूर्व अनुमान है, बीजेपी ये चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ रही है। इसके अलावा उसकी ओर से बीएस येदियुरप्पा का पूरा परिवार, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे स्टार प्रचारकों को उतारा गया है। यह तो हुई कर्नाटक की चुनावी स्थिति इसमें दिखाई तो यह दे रहा है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने के अवसर यादा है। परंतु यह चुनाव है, और चुनावों में अंतिम समय तक यह भविष्यवाणी करना किसी के लिए भी संभव नहीं है कि किस दल की सरकार बनेगी। ऐसा एक शब्द है चमत्कार वह कई राज्यों में आप और हम देख चुके हैं। अब कर्नाटक की बात को छोड़कर यदि हम मध्यप्रदेश की बात पर आते हैं, तो मध्यप्रदेश में भी अनेक प्रकार के सर्वे हुए हैं और उन सर्वे के जो नतीजे आए हैं,

उसमें कांग्रेस की स्थिति कमोबेश बीजेपी से अच्छी बताई गई है और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार से स्थितियां सामने आई है। उसी को देखते हुए कहा जा सकता है के मध्यप्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एकाधिक प्रवास मध्यप्रदेश में आयोजित हुए हैं। यह बात अलग है कि उनको विभिन्न कारणों से बुलाया गया है। परंतु निश्चित रूप से इन महान हस्तियों को बुलाने का कारण चुनावों में सरकार की स्थिति को या कहा जाए बीजेपी की स्थिति को मजबूत करना ही एक मात्र उद्देश्य है। लेकिन जिस प्रकार का एंटी इनकंबेंसी का मसला और अंडरकरेंट प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जैसा कि विभिन्न माध्यमों से उजागर होता रहता है, उससे यह कहा जा सकता है कि बीजेपी बहुत यादा कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत और वर्तमान सरकार ने भी अपनी पूरी ताकत मतदाताओं को लुभाने के लिए झोंक रखी है। अनेक योजनाएं लांच की जा रही हैं, और उनका जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, परंतु इसके बावजूद आम आदमी की जो प्रतिदिन की अपना जीवन जीने की जो समस्याएं हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि सरकार ने जो योजनाएं प्रारंभ की हैं, उसके लाभ के स्वरूप सरकार मध्यप्रदेश में बीजेपी की ही बनेगी।

अब यहां पर यह कहना समीचीन है की यदाकदा प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की बातें उठती रही हैं उन्हें यह कहकर शांत भी किया जाता रहा है कि मध्यप्रदेश का चुनाव वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अब यहां पर यह कहना भी समीचीन होगा कि बीजेपी के वर्तमान विधायक दल के नेता के अलावा एक और नेता फुल पावर में है, जिनके कारण वर्तमान नेतृत्व प्रदेश में चुनाव हार कर भी फिर से उपचुनाव में जीत कर सत्ता पर काबिज है, उनकी राज्य का क्या होगा? क्या वे 15-20 सीटों से संतुष्ट हो जाएंगे ?यदि ऐसा नहीं हुआ, तो यादा से यादा टिकट उनके खेमे में चले जाएंगे और जो शुद्ध भाजपा है, उसके कार्यकर्ता उसके नेता जो चुनाव में टिकट पाने के लिए कतार में लगे हैं, उनका क्या होगा? क्या उनमें बाद में उभरने वाले असंतोष को दबाने की रणनीति वर्तमान बीजेपी ने सोच रखी है? यदि हां तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं तो चुनावों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह कहा नहीं जा सकता। परंतु 13 मई को कर्नाटक के चुनावों के परिणाम आने हैं। इन परिणामों के पश्चात मध्यप्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तो समय का इंतजार करना उपयुक्त होगा, समय सभी के प्रश्नों का सही सही उत्तर देता है।

इतिहास के सबसे खराब निर्णयों के लिए जाना जायेगा वीडी शर्मा का कार्यकाल

विजया पाठक

दिसम्बर 2023 में प्रस्तावित मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश भाजपा में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बीते कुछ दिनों से लगातार प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों के पदों में बदलाव के बाद इस बात के भी कयास लगाये जाने लगे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जल्द ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद पर भी बदलाव कर सकता है। सूत्रों की मानें तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे वीडी शर्मा से प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व वापस लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वीडी शर्मा का दो वर्षीय कार्यकाल कुछ समय पहले ही खत्म हो चुका है और शर्मा को शीर्ष नेतृत्व में नया प्रदेश अध्यक्ष न मिलने की स्थिति में अध्यक्ष पद का दायित्व अतिरिक्त रूप से दे रखा था। लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के उद्देश्य के साथ भाजपा आलाकमान इस परिवर्तन को लेकर तैयारी में जुट गया है। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा को हटाये जाने को लेकर जो कारण बताये जा रहे हैं उनमें प्रमुख कारण है कि वीडी शर्मा से कार्यकर्ता बुरी तरह से खफा है। इसकी शिकायत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष तक से की है। बताया जा रहा है कि कुछ मजबूरी में बीजेपी हाईकमान वीडी शर्मा को हटा नहीं

विजयवर्गीय और तोमर मध्यप्रदेश में यही दोनों है बीजेपी के तारणहार

पा रहा है। लेकिन अब स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जल्द ही शर्मा को हटाया जा सकता है। शर्मा के कार्यकाल में मध्यप्रदेश से संगठन लगभग खत्म हो गया है। शर्मा के लड़कपन वाले फैसलों ने संगठन को निष्यि बना दिया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में संगठन की पकड़ कमजोर हुई है। राजनीतिक जानकारों का तो यहां तक कहना है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो 2023 के विधानसभा में बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जायेगी। कयास लगाये जा रहे हैं कि कभी भी शर्मा की छुटटी हो सकती है। इसके साथ ही यह बात भी सत्य है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इतिहास में सबसे खराब निर्णयों के लिए जाना जायेगा। अभी हाल ही में बीजेपी संगठन में बदलाव किये हैं। इस बदलाव में आशीष अग्रवाल को प्रदेश मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो मीडिया बेकग्राउंड से नहीं है। इस नियुक्ति की यादातर नेताओं ने विरोध दर्ज कराया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर की जगह आशीष अग्रवाल को प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया है। लोकेन्द्र पाराशर को भाजपा का प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा एबीवीपी के नौसिखियों को अपनी टीम में रखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि वीडी शर्मा लोकेन्द्र पाराशर को प्रदेश मंत्री बनाने के पक्ष में नहीं थे। दवाब में आकर पाराशर को यह दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा और भी कई ऐसी नियुक्तियां हैं जिनमें शर्मा ने अपनी चलाई है और कम तजुर्बोकारों को जगह दिलाई गई है। अपने कार्यकाल के दौरान वीडी शर्मा ने केवल अपने संसदीय चुनावी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रमुख पदों पर अधिक महत्व दिया। यही नहीं छोटे-छोटे शहरों के अनुभवहीन कार्यकर्ताओं को जिस तरह से वो पार्टी के प्रमुख जिम्मेदारियों से जोड़ने का काम कर रहे हैं उससे पार्टी आलाकमान पूरी तरह से खफा है।

विजयवर्गीय और तोमर हैं प्रमुख दावेदार

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिन तीनों नाम को लेकर चर्चा हो रही है उसमें कैलाश विजयवर्गीय एक प्रमुख दावेदार बताए रहे हैं। कैलाश को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपे जाने का प्रमुख कारण यह भी है कि विजयवर्गीय ने बीते पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बेहतर रणनीति बनाकर पार्टी को वहां अधिक सीटें दिलवाने में सफलता प्राप्त की। यही नहीं विजयवर्गीय का प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं, मंत्री, विधायकों से बेहतर तालमेल है। ऐसे में आलाकमान निचले स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए विजयवर्गीय को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। गौरतलब है कि विजयवर्गीय दिल्ली में बैठने के बावजूद भी लगातार प्रदेश में सयि रहते हैं और यहां के सियासी गणित से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गरम है। तोमर प्रदेश के सयि मंत्री हैं और भिंड, मुरैना सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में उन्हें महारात हासिल हैं। इसलिये पार्टी आलाकमान तोमर को भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। हालांकि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी नाम है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के नाम पर लगातार संशय बरकरार है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को नियंत्रित न कर पाने और पेड न्यूज छपवाने के मामले में कोर्ट में मामला लंबित है। ऐसे में मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा चुनावी समय में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।

शर्मा ने अपने परिवार वालों को बिठाया उच्च पदों पर

बताया जा रहा है कि शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष पद का प्रभाव दिखाते हुए अपने ससुर और ससुराल पक्ष के लोगों को बड़ा लाभ दिया है। उन्होंने अपने ससुर को कृषि

दीपक जोशी और राधेलाल बघेल ने थामा कांग्रेस का दामन

मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा पर धावा बोल दिया है। लगभग ढ़ाई साल पहले जैसे भाजपा ने साजिश रचकर कमलनाथ की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब भाजपा को यही दांव उलटा पड़ रहा है। दरअसल कमलनाथ ने भाजपा के नेहले पर दहला पटकते हुए एक–एक करके भाजपा के विकट गिराना शुरू कर दिया है। इसकी सबसे मजबूत कड़ी है पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्व. कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी और पूर्व विधायक राधेलाल बघेल। दीपक जोशी ने बीते दिनों भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। जोशी के कांग्रेस का दामन थामने से जहां एक

विश्वविद्यालय का कुलपति बनवा दिया तो पत्नी को उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दिलवाई है। यही नहीं प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह के साथ मिलकर खनन के क्षेत्र से उन्होंने अनाप-शनाप कमाई की है।

सत्ता और संगठन के पदाधिकारी नहीं सुहा रहे शर्मा को

प्रदेश अध्यक्ष का सबसे प्रमुख काम होता है सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल बिठाना। लेकिन वीडी शर्मा के साथ इसके बिल्कुल उलट है। विशृच्त सूत्रों की मानें तो वीडी शर्मा की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मनमुटाव चल रहा है। यह तो केवल बड़े

ओर भाजपा को बड़ा नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है वहीं जोशी के साथ मिलकर कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूती देगी। यही नहीं इससे पहले भी तीन से चार ऐसे कार्यकर्ता और विधायक जो भाजपा में लगातार उपेक्षित महसूस कर रहे थे उन्होंने कमलनाथ का साथ थाम लिया है।

भाजपा को उलटी पड़ सकती है तरकीब–राजनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो जोड़–तोड़ के गणित का सिलसिला भाजपा ने शुरू किया है। पहले महाराष्ट्र और फिर मध्यप्रदेश। दोनों ही रायों में भाजपा जिस साजिश के तहत जोड़–तोड़ की राजनीति को अंजाम दिया अब वही उसके लिये तकलीफ देह बनती जा रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा से जल्द ही और भी ऐसे कई चेहरे हैं जो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह से पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जाना भाजपा के लिये शुभ संकेत नहीं है। हांलिक ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाली भाजपा को फिलहाल यह अंदेशा है कि इस तरह से छोटे–छोटे कार्य़कर्ताओं के पार्टी छोड़कर जाने से उन्हें कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।

जोशी का जाना बड़ा झटका है– आज भाजपा जिस मुकाम पर है और उसे जमीन से उठाने में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कैलाश जोशी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जोशी जी भाजपा के नींव के पत्थर मानें जाते रहे हैं। लेकिन जोशी जी के स्वर्गवासी होने के बाद जिस तरह से भाजपा ने उनके परिवार को नजरअंदाज किया है उससे खफा दीपक जोशी ने आखिरकार भाजपा का दामन छोड़ दिया है। जोशी पिछली भाजपा सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री थे और भाजपा ने इस बार दोबारा सरकार बनने पर उन्हें मंत्री पद देना भी उचित नहीं समझा यही कारण है कि जोशी लगातार नाराज चल रहे थे और यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम कर भाजपा को बड़ा झटका दिया है।

भंवर सिंह शेखावत के बागी तेवर–पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने अपनी ही पार्टी पर कई आरोप लगाते हुए हमला बोला है। भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को कारण पार्टी की बदनामी हो रही है। जिन लोगों ने २०१८ में बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी उन्हें पार्टी में सम्मानित किया जा रहा है। शेखावत ने कहा कि यह टिकट की लड़ाई नहीं है। सम्मान की लड़ाई है। शेखावत का आरोप है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है। कांग्रेसियों के बीजेपी में आने से पार्टी की हालत खराब हुई है। पार्टी में अब जमीनी कार्यकर्ता और असली नेताओं की पूछ परख नहीं होती है। इसी बीच इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ से जब मीडिया ने जोशी को लेकर सवाल पूछा तो नाथ ने जवाब देते हुए कहा, आगे–आगे देखते जाइए होता है क्या? अभी तो बस ये ट्रेलर है पूरा फिल्म तो बाकी है। कमलनाथ के इस बयान से साफ है कि आगे भी और कई ऐसे नेता है जो कांग्रेस के साथ जुड़कर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।

वीडी शर्मा और नरोत्तम की कोशिशें रही विफल–दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, जोशी एक वरिष्ठ राजनेता हैं प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका है। मिश्रा ने आगे कहा, दीपक जोशी मेरे कैबीनेट सहयोगी रहे हैं वो एक सक्षम नेता के साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। हम उनके साथ हैं। वहीं जोशी को कांग्रेस में शामिल होने पर वीडी शर्मा भी एक्टिव हो गए हैं। शर्मा दीपक जोशी से संपर्क बनाए हुए हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, दीपक जोशी जल्द ही कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रदेश भाजपा को बड़ा नुकसान आगामी चुनाव में उठाना पड़ सकता है।

स्तर के नाम हैं। इसके अलावा भी स्थानीय स्तर पर यादातर क्षेत्रीय नेताओं से शर्मा की पटरी नहीं बैठ पा रही है। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से तो यहां तक खबरें है कि वीडी शर्मा और हितानंद में गाली गलौच तक हुई थी। वीडी शर्मा ने शुरू से ही सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी हजूरी की है। इसलिए कहा जा रहा है कि शर्मा पराम से नहीं परिमा से इस पद तक पहुंचे हैं। आज भी शर्मा को अपने आसपास ऐसे लोग पसंद हैं जो एसमैन की तरह खड़े रहते हैं। काबिल और होनहार लोगों की जरूरत नहीं है।

शर्मा की पत्नी की बढ़ रही सत्ता-संगठन में दखलअंदाजी- वर्तमान में वीडी शर्मा की पत्नी डॉ. स्तुति शर्मा की सत्ता-संगठन में काफी दखलअंदाजी बढ़ रही है। तमाम सियासी मामलों पर उनके ट्वीट पढ़े जा सकते हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि सियासी मुददों पर भी उनकी पत्नी सलाहकार की भूमिका में होती हैं। पोस्टिंग, ट्रांसफर में भी स्तुति शर्मा सक्रिय रहती हैं।

चुनाव के पहले अशोक गहलोत सरकार ने खेला मास्टर स्ट्रोक

समता पाठक

राजस्थान में दिसम्बर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के मददेनजर मौजूदा सरकार ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैदान में कूद चुके हैं। पिछले 30 वर्षो से राजस्थान में हर पांच साल बाद सरकार बदलने का मिथक चला आ रहा है। मगर मुख्यमंत्री गहलोत अगले विधानसभा चुनाव में इस मिथक को तोड़ कर फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना बजट पास करवाते समय राजस्थान में एक साथ 19 नए जिलों व बांसवाड़ा, पाली, सीकर तीन नए संभागों का गठन कर अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अभी राजस्थान में 33 जिले कार्यरत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसे ही राजनीति का जादूगर नहीं कहा जाता है। उन्हें जब भी मौका मिलता है अपनी राजनीतिक जादूगरी के बल पर विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देते हैं। विरोधी चाहे विपक्षी दलों के हो या उनकी खुद की पार्टी के हो। मौका मिलते ही वह किसी को नहीं बख्शते हैं। पिछले काफी समय से उन्हें अपनी ही पार्टी के अंदर तगड़े विरोध का

सामना करना पड़ रहा है। इसके उपरांत भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक-एक कर अपने सभी विरोधियों को राजनीतिक हाशिए पर पहुंचा दिया।

कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा भी खत्म हो गया है। अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पार्टी के सभी अब कहने लगे हैं कि एकजुटता से हम अगला विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं। उन्हें पता है कि एक तरफ उन्हें भाजपा सहित अन्य विरोधी दलों से मुकाबला करना होगा। यह पार्टी में व्याप्त अंदरूनी गुटबाजी को भी काबू में कर उन्हें चुनाव में कांग्रेस को बहुमत दिलाना होगा। गहलोत को पता है कि कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी के चलते आम जनता में पार्टी के प्रति संदेश नहीं जा रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए अशोक गहलोत प्रदेश में विकास मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गहलोत की झलक इस बार राजस्थान के आम बजट में भी देखने को मिली है। गहलोत ने अपने इस कार्यकाल के अंतिम बजट को पूरी तरह आमजन का विकास बजट बनाया है। बजट में प्रदेश के आम आदमी का पूरा ख्याल रखा गया है। उनके हित की बहुत सारी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। जिसका गहलोत पूरा राजनीतिक साथ सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के वृद्ध नागरिकों, विषया महिलाओं नियमों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।

लोगों को चुनावी राहत- प्रदेश के गरीब लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए गहलोत ने इस बार के बजट में 19 हजार करोड़ रुपए के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें उज्धवला योजना में शामिल प्रदेश के 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने व प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े एक करोड़ लोगों को प्रतिमा मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसके तहत हर पैकेट में 1 किलो दाल, 1 किला चीनी किलो नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध करवाए जिस पर राज्य सरकार 3 हजार करोड़ खर्च करेगी। गहलोत की यह योजना 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति व कृषि उपभोक्ताओं को 2

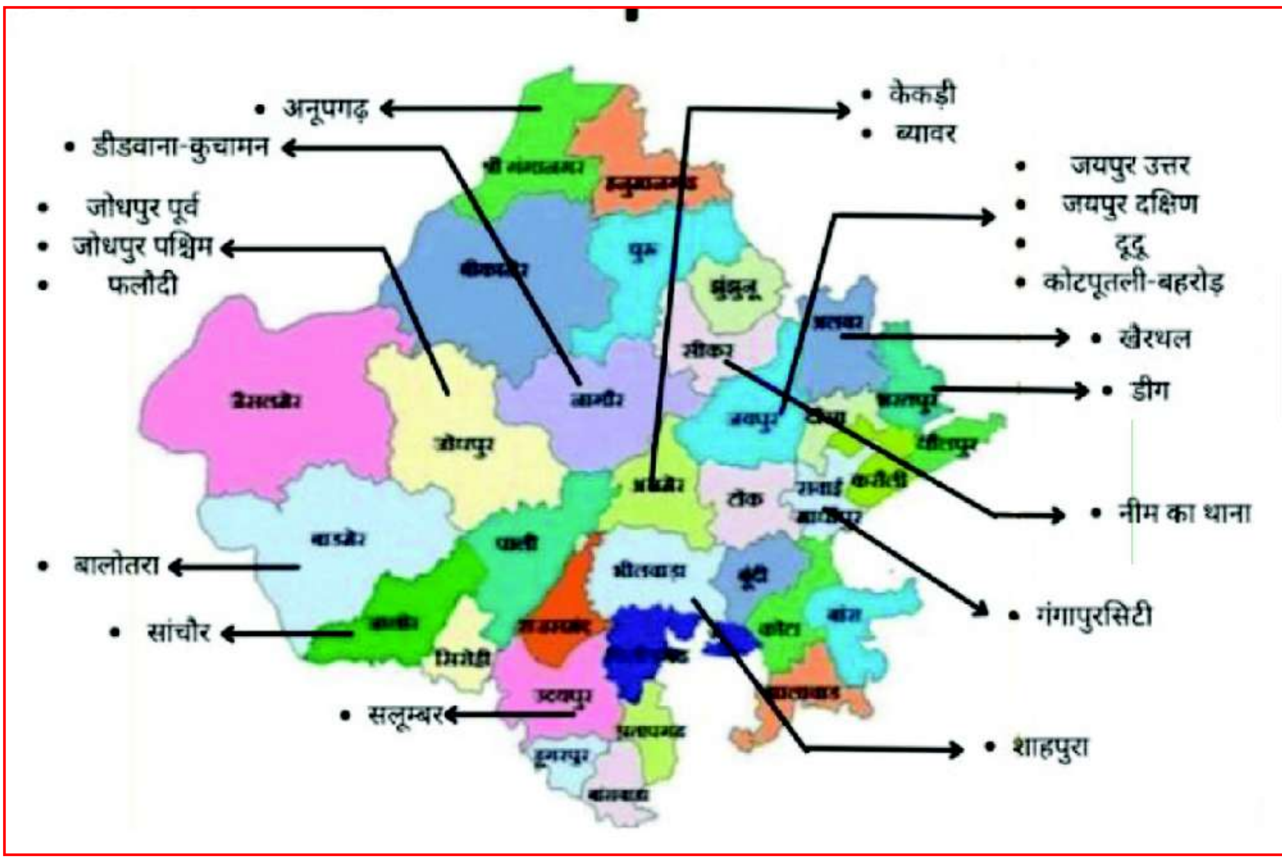

प्रदेश राजस्थान के 19 नये जिले

हजार यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने मुख्यमंत्री चिरजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का निशुल्क उपचार की सुविधा देना शामिल है। प्रदेश में सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में युवाओं से अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह बेरोजगार अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। बेरोजगार युवकों के लिए आगामी वर्ष में लाख नई भर्तियां करने की कर मुख्यमंत्री ने युवाओं को भी लुभाने का काम किया है। को मिलने कलों पेंशन की का प्रश्न बनी हुई है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने महिलाओं-छात्राओं को आने वाले रक्षाबंधन पर 40 लाख स्मार्ट फोन देने की बड़ी घोषणा की है। गहलोत ने बजट के दिन उज्ध्वला से जुड़ी महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की थी। यह प्रदेश की महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति है। महिलाओं को फोकस करते हुए गहलोत ने बजट में राजस्थान रोडवेज की साधारण श्रेणी की बसों में राजस्थान सीमा के भीतर बढ़त की थीम के साथ गहलोत द्वारा पेश बजट ने विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की चर्चा पर जवाब देते हुए कांग्रेस आलाकमान को भी संदेश दे दिया है कि आज भी उनमें सबको साथ लेकर चलने की क्षमता बरकरार है। राजस्थान कांग्रेस में वही एकमात्र ऐसे नेता है जो विरोधियों को पटकनी दे सकते हैं। विरोधी दल कितना भी हल्ला मचाए प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को रोकने की ताकत उनमें ही है। हर बार

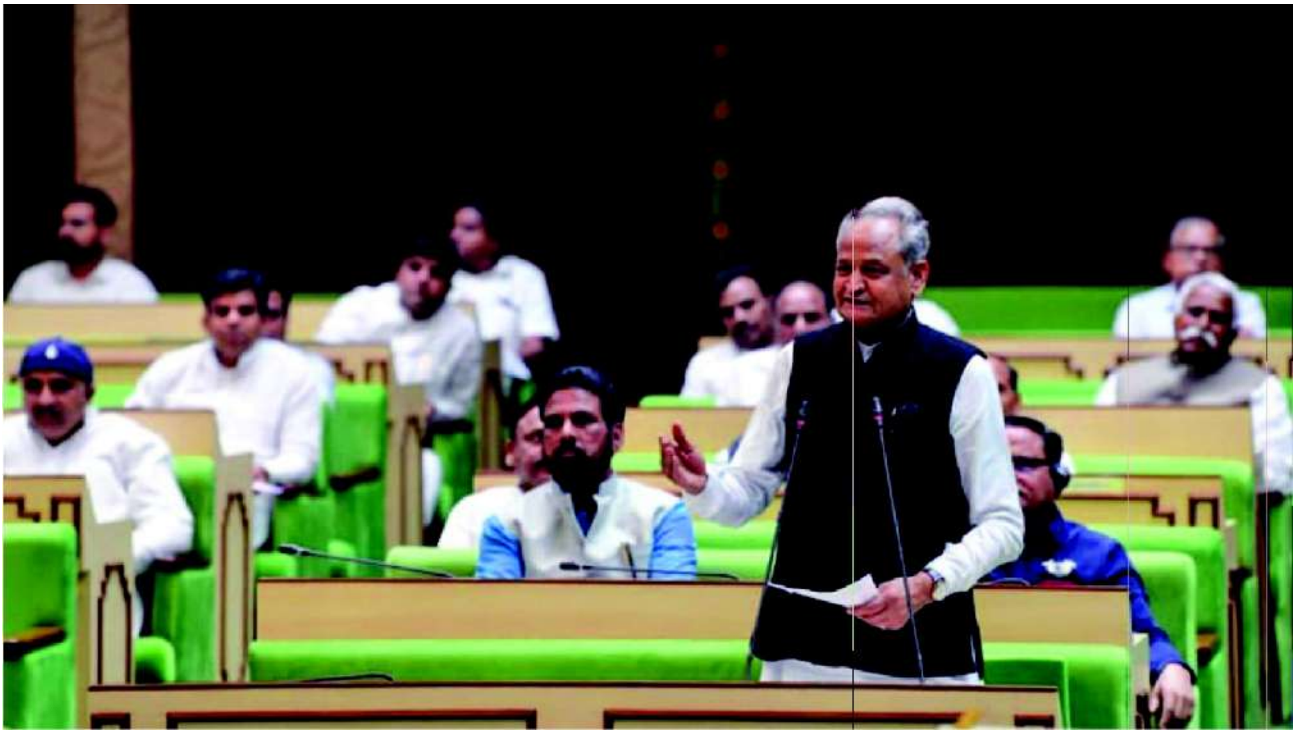

राशि में भी बढ़ोतरी को थी। अपने विकास के एजेंडे के तहत ही मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण की एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इस नहर परियोजना के पूरा होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लोगों को पीने का पानी तो मिलेगा ही साथ ही 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए जीवन-मरण महिलाओं का बस किराया आधा कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा नई लीक खींचकर लक्ष्य हासिल करने में विश्वास रखते हैं। इसी को मध्य नजर रखते हुए इस बार का आम बजट पूरी तरह प्रदेश के आमजन की जन आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से बनाया गया है। इसमें आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है। चुनावी साल में सभी सरकारें लोक लुभावन बजट पेश करती हैं। इस बार बचत, राहत और सत्ता बदलने का मिथक भी वह इस बार तोड़ देंगे। इन्हीं सब बातों को देखते हुए अब लगने लगा है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आलाकमान उन्हें पूरी तरह फ्री हैंड देकर राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। अशोक गहलोत ने अपने जादुई पिटारे से सभी लोग लुभावनी घोषणाये तो कर दी है। अब देखना है चुनाव तक उन पर कितना अमल हो पाता है। यदि अशोक

गहलोत अपने मिशन में कामयाब होते हैं तो उन्हें चौथी बार मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पायेगा।

गौरतलब है कि एक नवंबर 1956 को राजस्थान गठन के समय कुल 26 जिले थे। 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग कर धौलपुर प्रदेश का 27 वां जिला बना था। 10 अप्रैल 1991 को एक साथ 3 जिले कोटा से अलग होकर बारां, जयपुर से अलग होकर दौसा व उदयपुर से अलग होकर राजसमंद जिले का गठन हुआ था। 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला बना था। 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग होकर करौली को 32 वां जिला बनाया गया था। 26 जनवरी 2008 को उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा से अलग होकर प्रतापगढ़ 33 वां जिला बना था। 2008 में प्रतापगढ़ के बाद से राज्य में कोई नया जिला नहीं बन पाया। वर्तमान में राजस्थान की आबादी 8 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 40 सालों में प्रदेश कि आबादी तो दोगुनी हो गई लेकिन जिले केवल सात ही बढ़े हैं। 1981 तक राजस्थान में 26 जिले थे तब राजस्थान की जनसंख्या करीब 3.6 करोड़ थी। आज के समय में आबादी 08 करोड़ से भी यादा है, लेकिन जिले 33 ही बन पाए। आबादी की तरह जिलों की संख्या नहीं बढ़ी। राजस्थान में अंतिम जिला 15 वर्ष पूर्व प्रतापगढ़ बना था। उसके बाद से प्रदेश में लगातार नए जिले बनाने की मांग उठती रही थी। मगर राजनीतिक विरोध की संभावना के चलते किसी भी सरकार ने नए जिलों के गठन का जोखिम उठाना राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं माना और नये जिलों का गठन टलता रहा। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का पहला व आबादी के हिसाब से सातवा सबसे बड़ा प्रदेश है। जिलों की कमी के चलते प्रदेश में प्रशासनिक कार्यो के लिए लोगों को दूर-दूर भटकना पड़ता है। कई क्षेत्रों में तो जिला मुख्यालय 150 किलोमीटर की दूरी तक स्थित होने से आमजन को बहुत ही परेशानी उठानी पडती है। प्रदेश के आमजन की परेशानियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ 19 नये जिलों का गठन कर प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसका लाभ कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलना तय माना जा रहा है। देश में एक साथ सबसे अधिक जिलों के गठन का रिकॉर्ड भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम हो गया है। अब तक किसी भी प्रदेश में एक साथ 19 जिलों का गठन नहीं हुआ है। प्रदेश में बनाये गए नए जिलों में जयपुर जिले को तोड़कर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपूतली जिला बनाया गया है। जोधपुर को तोड़कर जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी में बांटा गया है। श्रीगंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर से बालोतरा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, भरतपुर से डीग, नागौर से डीडवाना-कुचामनसिटी, सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी, अलवर से खैरथल, सीकर से नीम का थाना, उदयपुर से सलूंबर, जालोर से सांचोर और भीलवाड़ा से शाहपुरा को काटकर नया जिला बनाया गया है। वहीं उदयपुर को काटकर बांसवाड़ा, जोधपुर को काटकर पाली व जयपुर को काटकर सीकर नए संभाग बनाए गए हैं। इन संभाग मुख्यालयों के तहत कौन-कौन से जिले काम करेंगे यह अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। नये संभागों के गठन में भी क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है। शेखावाटी क्षेत्र से सीकर, मारवाड़ क्षेत्र से पाली और आदिवासी बहुल मेवाड़ क्षेत्र से बांसवाड़ा को नया संभाग बनाया गया है। नए जिलों के गठन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक समर्थकों के साथ विरोधियों को भी साधा है। जहां कांग्रेस कमजोर है वहां भी नये जिलों की घोषणा की गई है। ब्यावर में लंबे समय भाजपा के शंकर सिंह रावत जीत रहें हैं। भाजपा राज में ब्यावर जिला नहीं बन पाया। गहलोत ने ब्यावर को जिला बना दिया। जिसे आगे चुनाव में कांग्रेस भुनाएगी। पाली, जालोर और सिरोही में भी कांग्रेस बहुत कमजोर है। पाली को संभाग मुख्यालय बनाना और सांचैर को जिला बनाना भी गहलोत का उस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। फलोदी, बालोतरा को भी जिला बनाकर गहलोत ने अपनी छवि को मजबूत किया है।

कर्नाटक चुनाव

त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार

224 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्ताधारी भाजपा को 82-87 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। दिलचस्प बात ये है कि कांग्रेस को भी 82-87 सीट ही मिलती दिखाई दे रही हैं। राज्य की सत्ता में रह चुकी जेडीएस को 42-45 सीटें मिल सकती हैं।

दिनेश चौबे

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 इसी महिने हो रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस में कड़ी टक्र र होने की बात कही जा रही है। सत्ताधारी भाजपा मोदी लहर के सहारे एक बार फिर से राज्य में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है तो कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर का सहारा है। वहीं, जेडीएस भी राज्य में मजबूत ताकत बनने के लिए जोर लगा रही है। राज्य में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगाया गया है। खास बात ये है कि इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों को लगभग बराबर सीट मिलने की संभावना जाहिर की गई है। 224 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्ताधारी भाजपा को 82-87 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। दिलचस्प बात ये है कि कांग्रेस को भी 82-87 सीट ही मिलती दिखाई दे रही हैं। राज्य की सत्ता में रह चुकी जेडीएस को 42-45 सीटें मिल सकती हैं। एक बार फिर से जेडीएस की

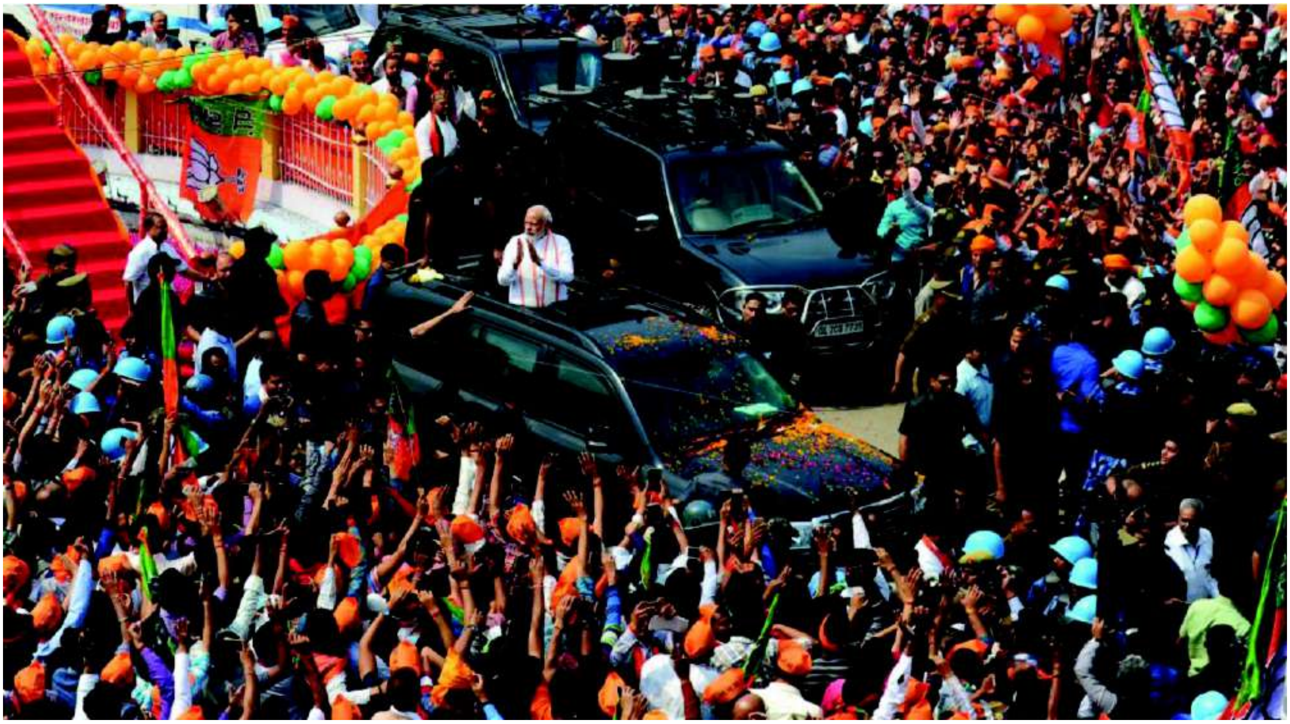

कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव पूर्व घोषणाओं में सबको मात देती लग रही है। कांग्रेस ने मुफ्त की रेवड़ियों का पिटारा खोला है। भाजपा तो बैकफुट पर है ही। चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस नेता हर दूसरे या तीसरे दिन कोई नई घोषणा कर रहे हैं।

भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने से रह गई थी। भाजपा को 104 सीटें मिली थीं। तब 80 सीटें पाने वाली कांग्रेस ने 37 सीटें पाने वाली जेडीएस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सत्ताधारी भाजपा विजय संकल्प रैली निकाल रही है। चुनाव से पहले भाजपा में टिकट को लेकर घमासान देखने को मिला था। इस बार कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई तो फिर त्रिशंकु विधानससभा बनेगी, जिसमें वह कांग्रेस और भाजपा दोनों से मोलभाव कर सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव पूर्व घोषणाओं में सबको मात देती लग रही है। कांग्रेस ने मुफ्त की रेवड़ियों का पिटारा खोला है। भाजपा तो बैकफुट पर है ही। चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस नेता हर दूसरे या तीसरे दिन कोई नई घोषणा कर रहे हैं। इतना ही नहीं कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह गारंटी पत्र देगी। पार्टी की ओर से दस्तखत किया गया एक गारंटी पत्र सभी नागरिकों को दिया गया है, जिसमें लिखा है कांग्रेस अपना वादा पूरा करेगी। आम नागरिकों को यकीन दिलाने के लिए कांग्रेस गारंटी पत्र दे रही है। पहले ही राज्य में सक्रिय पार्टियों में आपाधापी लगी हुई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंट्री ने उसकी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप संयोजक केजरीवाल ने कर्नाटक में अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अपनी पहली जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाते हुए जनता से एक आम आदमी पार्टी को पांच साल के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का मौका देने की अपील की थी। केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहते है कि राज्य में 40 फीसदी कमीशन की सरकार

चल रही है।

येदियुरप्पा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 224 विधानसभा सीटों में 130-140 सीटें जीतने का लक्ष्य रख दिया है। पार्टी को बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए और 2018 के विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा के चेहरे पर चुनाव लड़कर 106 सीटें ही ला सकी थी। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने और उन्हें अल्पमत में होने के कारण हटना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से जद(एस) ने सरकार बनाई। एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ महीनों के बाद आपरेशन लोटस-2 के बाद वह फिर राय सरकार के मुखिया बन गए थे। यही नहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पहली बार कर्नाटक सरकार की विकास योजनाएं गिनाने की जगह मोदी और येदियुरप्पा के चेहरे पर वोट मांगा था। उन्होंने बेल्लारी की चुनावी रैली में कहा था, मेरी आपसे अपील है कि प्रधानमंत्री मोदी और येदियुरप्पा में अपना भरोसा बनाए रखें और भाजपा को फिर से सत्ता में लौटाएं। उसके बावजूद ऐसे कई कारण है जिसके कारण भाजपा को कर्णाटक चुनाव की लड़ाई कठिन लग रही है हालाँकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 48 दिन के भीतर पांच बार कर्नाटक राज्य का दौरा कर चुके है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार कर्नाटक को अहमियत दे रहे हैं। अमित शाह ने पार्टी नेताओं को चुनाव जीतने के मंत्र दिए। बूथ स्तर पर तैयारियों को तेज करने के सूत्र बताने के साथ आपसी गुटबाजी को शांत करने की कोशिश में लगे हैं। भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जिन सीटों पर 2018 में हारे थे, उसे इस बार जीतने की रणनीति बनाई है। भाजपा मुख्यालय के एक नेता का दावा है कि 2023 में पुराना मैसूर क्षेत्र से भाजपा को 20 सीटें अधिक मिलने वाली हैं। हालांकि पुराना मैसूर का इलाका वोक्कालिगा बहुल है। भाजपा नेता डा. सीएन अश्वथनारायण भी वोक्कालिगा हैं। वोक्कालिगा को साधने के लिए भाजपा ने अश्वथनारायण को काफी अहमियत दी है। कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार भी वोक्कालिगा हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनका परिवार वोक्कालिगा है। पुराने मैसूर में जबरदस्त पकड़ रखता है। डीके शिवकुमार भी कांग्रेस के बेहद प्रभावी नेता हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में पुराने मैसूर की 64 सीटों में भाजपा को केवल 11 मिली थीं। 17 कांग्रेस ने जीती थी। 37 जद (एस) के पाले में गई थी। जद (एस) कुल 37 सीटें जीतने में सफल रहा था। भाजपा की कोशिश इसी क्षेत्र में विपक्ष को पटखनी देखकर कम से कम 30-35 सीटें जीतने की है। वैसे भाजपा के नेता बातचीत में मानते हैं कि इस बार कर्नाटक में मुकाबला दिलचस्प होगा। हालांकि उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस की अंदरुनी कलह का बड़ा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कर्नाटक में भी सरकार और भाजपा

की स्थिति अच्छी नहीं है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले भाजपा अपनी सभी कमियों को दूर कर लेना चाहती है। भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि उसे विपक्ष की कमजोरी और विपक्षी दल में अंतर्कलह का भी लाभ मिलेगा। कहते हैं कि कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया में भी प्रतिस्पर्धा चल रही है। सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से आते हैं। डीके शिवकुमार की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है। उनकी लोकप्रियता एचडी कुमारस्वामी को भी भीतर से परेशान करती है। डीके शिवकुमार वैसे भी पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा परिवार से करीबी संबंधों के लिए जाने जाते हैं। सिद्धारमैया कैम्प डीके शिवकुमार को रोकने के लिए पूर्व मंत्री और लिंगायत नेता एमबी पाटील को आगे कर देते हैं। भाजपा को लग रहा है कि कर्नाटक में उसे इसका फायदा मिलेगा।

कर्नाटक में लिंगायत ही नहीं उसके बाद वोक्कालिगा बड़ा समुदाय है। वोक्कलिगा समुदाय के वोटरों का दक्षिण कर्नाटक के जिले जैसे मंड्या, हसन, मैसूर, बेंगलुरु (ग्रामीण), टुमकुर, चिकबल्लापुर, कोलार और चिकमगलूर में दबदबा है। राय की आबादी में ये 16 प्रतिशत हैं। ये जेडीएस के परंपरागत समर्थक माने जाते हैं। लिंगायत को ज्यादा तरजीह देने के कारण ये समुदाय भाजपा से खफा रहती है। कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए भाजपा जेडीएस से गठबंधन कर वोक्कालिगा समुदाय के दबदबे वाले पुराने मैसूर क्षेत्र की 89 सीटों के चुनावी समीकरण को साध सकती है। पिछली बार भाजपा को इनमें सिर्फ 22 सीटों पर ही जीत मिली थी। कांग्रेस को 32 और जेडीएस को 31 सीटों पर जीत मिली थी। अगर इन इलाकों में भाजपा का प्रदर्शन कुछ और बेहतर होता तो उसे स्पष्ट बहुमत आसानी से हासिल हो जाता। दक्षिणी कर्नाटक में इस बार राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा मिलने की आस है। बोम्मई सरकार को वोक्कालिगा समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे से भी निपटना होगा। ये समुदाय अपने लिए 4 से बढ़ाकर 12 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहा है। चुनाव से पहले अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा को इनके नाराजगी का खामियाजा भगतना पड़ सकता है। पुराने मैसूर के इलाकों में भाजपा अपनी कमजोरी पर ध्यान दे रही है। वो चाहती है कि यहां की 70 से ज्यादा सीटों पर जीत मिले। कर्नाटक में सबसे बड़ी आबादी दलित मतदाताओं की भी है। कर्नाटक में अनुसूचित जाति की आबादी 23त्न है। यहां विधानसभा की 35 सीटें इस समुदाय के लिए आरक्षित है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में दलितों का बड़ा योगदान रहा था। भाजपा को इस समुदाय का 40 फीसदी वोट मिला था। जबकि 2013 में कांग्रेस को 65 फीसदी दलित वोट मिले थे। इससे जाहिर है कि इस बार भाजपा को बड़ी जीत हासिल करने के लिए दलितों का सहयोग चाहिए। मल्लिकार्जुन खरगे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने

से कर्नाटक का दलित वोट बैंक कांग्रेस की ओर लामबंद नहीं हो, इसकी ओर भी भाजपा को ध्यान देना होगा। सवाल यह भी है कि क्या आदिवासी फिर से कमल का देंगे साथ? क्योंकि कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 7प्रतिशत है। उनके लिए 15 सीटें आरक्षित हैं। ये मुख्य तौर से मध्य और उत्तरी कर्नाटक में केंद्रित हैं। पिछली बार भाजपा को इनका साथ मिला था। इस समुदाय के 44 फीसदी वोट के साथ भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कर्नाटक में एसटी के लिए आरक्षित दोनों सीट पर जीत हासिल की थी। आरक्षित सीटों के अलावा मलनाड और तटीय जिलों में कुछ सीटों पर आदिवासी वोट निर्णायक साबित होते हैं। इस समुदाय में कांग्रेस की भी अच्छी पकड़ है। अगर भाजपा कर्नाटक को अपना मजबूत किला बनाना चाहती है तो उसे आदिवासियों का वोट बंटने से रोकना होगा। पिछड़े वर्ग को साथ लाने की भी एक चुनौती है जबकि दक्षिण के रायों में चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही इस बार जुलाई में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई थी। ये तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे रखकर भाजपा हर वर्ग के वोट को साधने की कोशिश करेगी। भाजपा इसके लिए डबल इंजन के मंत्र भी इस्तेमाल करेगी। हालांकि उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती कर्नाटक के पिछड़ी जातियों को अपने साथ लाना है। भाजपा को ये अच्छे से पता है कि बिना जाति समीकरण को साधे कर्नाटक में वो बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकती।

गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें है और सत्ता के लिए 113 सीटों की जरुरत होती है। विधानसभा चुनाव के नजरिए से कर्नाटक को 6 भागों में बांटा जा सकता है। हैदरबाद से सीमाएं जुड़ने वाला क्षेत्र हैदराबाद कर्नाटक में 40 सीटें आती हैं। बॉम्बे कर्नाटक यानी महाराष्ट्र से लगे इलाकों में 50 सीटे, तटीय क्षेत्रों में 19, मैसूर के इलाके में 65 सीटें आती हैं। वहीं सेंट्रल कर्नाटक में 22 और बेंगलुरु में 28 सीटें आती हैं। पिछली बार 2018 में हुए चुनाव में भाजपा 104 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। भाजपा को 36.35त्न वोट मिले थे। कांग्रेस सबसे यादा वोट 38.14त्न लाने के बावजूद 80 सीट ही ला सकी थी और जेडीएस को 37 सीटों पर जीत मिली थी। 2013 के चुनाव में भाजपा को महज 40 सीटें मिली थी। इस लिहाज से उसे 2018 के चुनाव में 64 सीटों का फायदा मिला था। 2013 के मुकाबले 2018 में भाजपा के वोट बैंक में करीब दोगुना का इजाफा हुआ था। हालांकि त्रिकोणीय समीकरण बनने की वजह से भाजपा बहुमत हासिल करने में नाकाम रही थी। वहीं 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 42 सीटों का नुकसान हुआ। ऐसे तो भाजपा कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ना चाहेगी। लेकिन एक फैक्टर है जिसे भाजपा रोकना चाहेगी। कांग्रेस-जेडीएस का चुनाव पूर्व गठबंधन भाजपा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस को मिलाकर 117 सीटें आई थी। भाजपा को 36.53 प्रतिशत, कांग्रेस को 38.14 प्रतिशत और जेडीएस को 18.3 प्रतिशत वोट मिले थे। वोट शेयर के विश्लेषण से साफ है कि पिछली बार

कांग्रेस-जेडीएस को मिलाकर 56 फीसदी से यादा वोट मिले थे। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने अक्टूबर 2022 में ही एलान कर दिया था कि वे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं और भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस जेडीएस से गठबंधन का दबाव बना सकती है।

बिना सारथी के केजरीवाल !

अमित राय

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए सत्येंद्र जैन और मनीष सिसौदिया का जेल जाना किसी आघात से कम नहीं है। केजरीवाल के लिए दोनों की अहमियत काफी है। कह सकते हैं कि यह दोनों की केजरीवाल के बायें और दायें हाथ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विसार और विकास के मामलों में इनका काफी योगदान रहा है। लेकिन आज केजरीवाल के दोनों रणनीतिकार जेल में हैं। केजरीवाल सियासत के मैदान में अकेले पड़ गये हैं। दोनों का जेल जाना बहुत बड़ा झटका है। देश के तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आप पार्टी लगभग सभी राज्यों में पैठ बनाकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। आप के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए इस समय पार्टी को एक बेहतर संगठन कर्ता की आवश्यकता है, जो संगठन को और मजबूत कर सके। वर्तमान समय में केवल केजरीवाल के भरोसे आप की सियासत चल रही है। उसके दो प्रमुख सिपहसलारकार जेल में हैं। मनीष सिसोदिया तो अरविंद केजरीवाल के साथ तब से हैं जब वो लोग सूचना के अधिकार पर काम कर रहे थे और दिल्ली में आप की सरकार बन जाने के बाद तो अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक रूप से मनीष सिसोदिया अपरिहार्य से हो गये। चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो

अरविंद केजरीवाल गुजरात में जमे रहने के बावजूद महज सात सीटें जीत पाये और दिल्ली को मनीष सिसोदिया के भरोसे छोड़कर भी अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में पार्टी का पताका तो फहराया ही। अब तो मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही है। ये मनीष सिसोदिया पर खुद से भी ज्यादा भरोसा ही रहा है जो अरविंद केजरीवाल उनको डिप्टी सीएम बनाने के बाद अपने हिस्से के विभाग भी सौंप दिये थे और सत्येंद्र जैन के जेल चले जाने के बावजूद मनीष सिसोदिया के भरोसे ही उनको मंत्री बनाये रखा। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल ये है कि मनीष सिसोदिया, सिर्फ साथ ही काम नहीं करते थे। सिर्फ साये की तरह हर सुख दुख में मौजूद ही नहीं रहते थे। सिर्फ अरविंद केजरीवाल के हिस्से की प्रशासनिक जिम्मेदारियां ही नहीं संभालते थे। वो तमाम मामलों में सलाहकार भी होते हैं। अच्छे बुरे फैसलों में साथ साथ रणनीतिकार भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात

मनीष सिसोदिया पर खुद से भी ज्यादा भरोसा ही रहा है जो अरविंद केजरीवाल उनको डिप्टी सीएम बनाने के बाद अपने हिस्से के विभाग भी सौंप दिये थे और सत्येंद्र जैन के जेल चले जाने के बावजूद मनीष सिसोदिया के भरोसे ही उनको मंत्री बनाये रखा। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल ये है कि मनीष सिसोदिया, सिर्फ साथ ही काम नहीं करते थे। सिर्फ साये की तरह हर सुख दुख में मौजूद ही नहीं रहते थे।

अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार भी रहे हैं। वहीं सतेन्द्र जैन भी केजरीवाल के प्रमुख सहयोगी के रूप में पहचाने वालों में हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से लायी गयी शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर ऐसी कई योजनाएं हैं, जिनकी पहल सत्येंद्र जैन की तरफ से हुई क्योंकि आइडिया भी तो उनके ही थे। आपको हैरानी हो सकती है। दिल्ली की जिस शिक्षा व्यवस्था को क्रांतिकारी बताया जा रहा है, जिसके नाम पर शुरू से लेकर अभी तक मनीष सिसोदिया का आम आदमी पार्टी की तरफ से बचाव किया जा रहा है। वो मूल आइडिया मनीष सिसोदिया का नहीं बल्कि सत्येंद्र जैन का बताया जाता है। चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो या फिर मुफ्त में बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधायें देने की। बताते तो यही हैं कि ओरिजिनल आइडिया सत्येंद्र जैन की तरफ से पहले सामान्य बातचीत और फिर औपचारिक मीटिंग में सत्येंद्र जैन की तरफ

से ही सामने आये थे।

साल दर साल बीतते गये, और मनीष सिसोदिया बिलकुल किसी हमसफर की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ बने रहे, लेकिन कुछ देर के लिए उसमें ब्रेक का वक्त आ गया है और भले ही वो बोल कर गये हों कि जल्दी ही लौटेंगे, लेकिन ये तय करने वाला तो कोई और ही है। ये जल्दी भी हो सकता है, और लंबा वक्त भी लग सकता है। अरविंद केजरीवाल के लिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की अलग अलग अहमियत है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क भी है। क्योंकि दोनों ही अलग अलग तरीके से अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे हैं और बड़े ही मजबूत खंभे की तरह बगैर कुछ सोच विचार या सवाल के चुपचाप पीछे खड़े रहे हैं। कामकाज के हिसाब से देखें तो जितना गहरा संबंध अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में लगता है, करीब करीब वैसा ही रिश्ता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन में नजर आता है।

वैसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका तो अरविंद केजरीवाल और उनके सारे साथी तभी से जताने लगे थे जिस दिन पहली बार सीबीआई की टीम के छापे पड़े थे और यही वजह रही कि जिस रणनीति पर आम राय बनी थी, मनीष सिसोदिया खुद भी बार बार गिरफ्तारी की आशंका जताते आ रहे थे। आशंका ही नहीं, बल्कि मनीष सिसोदिया तो बार बार नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज भी कर रहे थे कि गिरफ्तार करके दिखायें। लेकिन तभी गुजरात चुनाव और एमसीडी चुनाव होने लगे और फिर सिसोदिया के केस में सीबीआई की तरफ से फील्ड वर्क कम और ऑफिस में काम यादा होने लगा। मनीष सिसोदिया के बचाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का शिक्षा का मॉडल सामने रखा। शराब नीति को लेकर जब मनीष सिसोदिया घिरे तो अरविंद केजरीवाल और साथियों ने स्कूली बच्चों के भविष्य से जोड़ कर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी की तरफ से दिल्ली के नेता बार बार आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को भ्रष्टाचार में डूबा साबित करने में जुट गये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ।

कल तक केजरीवाल और सिसोदिया की जोड़ी खुद को छोड़कर देश के सारे ही नेताओं को भ्रष्ट बताती रही, आज दोनों के सामने खुद को ही पाक साफ साबित करने की चुनौती आ खड़ी हुई और ये शायद केजरीवाल और सिसोदिया को अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाये रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो केजरीवाल कल तक कहते थे कि संसद में बैठे सारे ही डकैत और बलात्कारी हैं। जो केजरीवाल किसी पर भी भ्रष्ट होने की तोहमत मढ़ दिया करते थे। जो केजरीवाल खुद को देश का सबसे इमानदार मुख्यमंत्री होने का सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले होने का दावा करते रहे। राजनीति में आये कुछ ही साल होने के बाद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने साथियों पर लगे आरोपों से उनका कैसे बचाव करें तो कैसे करें? फिलहाल अरविंद केजरीवाल के सामने ये भी एक चैलेंज है कि वो लोगों की नजरों में बने रहें, नजरों से उतर जाने का खतरा भी अभी सबसे ज्यादा है।

मनीष सिसोदिया के बगैर अरविंद केजरीवाल के लिए रूटीन का कामकाज ही नहीं राजनीतिक लड़ाई भी काफी मुश्किल होगी और अगर कानूनी या किसी राजनीतिक तरीके से मनीष सिसोदिया को जल्दी बाहर नहीं ला सके तो 2024 के सपने तो शेप लेने से पहले ही बिखर जाएंगे। इस समय दोनों का बाहर आना आप के लिए बहुत आवश्यक है। 2024 की बिसात बिछाने केलिए मनीष सिसौदिया और सतेन्द्र जैन जैसे कर्मठ रणनीतिकारों को होना जरूरत है।

भारतीय पर्व-परम्पराओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग है गौ-वंश

भारतीय सनातनी, हिन्दू परिवारों में होने वाले छोटे से छोटे आनुष्ठानिक कार्यो से लेकर बड़े से बड़े आयोजनों में गाय के पूजन से लेकर उसके सभी उत्पाद जैसे दूध, दही, घृत, गोबर, गौ-मूत्र (पञ्चगव्य) की उपयोगिता अनिवार्य सुनिश्चित की गई है। हिन्दू घरों में प्रतिदिन चूल्हे पर बनने वाली प्रथम रोटी को गाय की रोटी माना गया है, इसे ही हम गौ-ग्रास कहते हैं। प्रातःकाल उठ कर हिन्दू परिवार के सदस्य सर्वप्रथम घर में बनी गौ-शाला गौ-शाला में जाकर गाय को प्रणाम कर उसे हरी घास आहार के रूप में समर्पित कराते हैं। गायों का गोबर उठा कर उसे व्यवस्थित रीति से सुरक्षित करना दिनचर्या का अंग होता है। यह दिनचर्या आज भी भारतीय पारम्परिक परिवारों में देखी जा सकती है। प्रातःकाल जागरण से लेकर गौ-दोहन, गौ-चारण और सायंकाल गोचर कर गायों का समूह में घर में वापस आने की बेला को पवित्र गोधूलि बेला माना गया है।

गौ-सेवा को अत्यंत पवित्र कर्त्तव्य हमारे भारतीय धर्म शास्त्रों में व्याख्यायित किया गया है। गाय को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। गाय का यह महत्त्व कोटि-कोटि हिन्दू जन-मानस में सदियों से रचा-बसा है। इसी कारण गाय और सम्पूर्ण गौ-वंश को हम आस्था और श्रद्धा के केंद्र में रखते हैं।

गाय को भारत की आर्थिक समृद्धि का आधार माना गया है, गौ-वंश को भारतीय कृषि का आधार, पर्यावरण की संरक्षिका, भौतिक विज्ञान के अनुसंधान का केंद्र, आयुर्वेद का आधार सहित विभिन्न विधाओं को प्रभावित करने वाला भारतीय गौ-वंश की महिमा अपार है। भारतीय पारम्परिक पर्वो की श्रंखला में अनेक पर्व तो सीधे गौ-वंश के लिये ही हैं जैसे वत्स-द्वादशी, गोपाष्टमी तथा दीपावली के दूसरे दिन गोवर्द्धन पूजा का पर्व।

भारतीय पारम्परिक पर्वो में छिपा है वैज्ञानिक तथ्य

भारतीय पर्वो को मनाने की अपनी एक विशिष्ट शैली है, जिसमें तिथि, नक्षत्र, दिन, योग एवं पर्व केंद्रित रीति-रिवाज एवं पर्व

का देवता, देवी एवं उनके पूजन, स्मरण आदि का सामाजिक महत्त्व तथा उनमें छिपा विविध प्रकार का अन्वेषण जनित विज्ञान अवस्थित है। अधिकतर विज्ञान का वह पक्ष जिसे हम बोलचाल की भाषा में मनोविज्ञान कहते हैं; पर्वो को आयोजित करने एवं उनके मनाने में जन-मन का अनुरंजन, विनोद, आनंद, उल्लास, मानसिक उमंग ये सब मनोविज्ञान के विविध आयाम हैं। इसकी पुष्टि भारतीय मान्यताओं में प्रकृति की अष्टधा रूपों में अभिव्यक्त है।

भूमिरापोनलो वायुःखं मनोबुद्धिरेव च।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।

की ही अभिव्यक्ति है।

पर्वो की प्रासंगिकता उनके आरम्भिक काल में जितनी थी, आज भी वे सभी भारतीय प्राचीन पर्व उतने ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है; उनके वर्तमान समय में युगानुकूल, सामयिक और नवाचारित स्वरूप में प्रस्तुत कर उन्हें अत्यधिक प्रासंगिक बनाना समय की अनिवार्यता है।

गौ-वंश कभी भी अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं होता

आज किसान या गौ-पालकों द्वारा गोवंश को बेसहारा किया जा रहा है। उन्हें यह कह कर घर से बाहर किया जा रहा है कि गाय दूध नहीं दे रही है और बैल की खेती-किसानी में उपयोगिता नहीं रही। कारण अब कृषि का यांत्रिकीकरण हो गया है जबकि तथ्य इसके विपरीत है। गाय दूध दे रही या नहीं, बैल कृषि कार्य करने योग्य है या नहीं गौ-वंश को अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं कह सकते। गौ-वंश से हमें गोबर और गौ-मूत्र जीवन भर मिलता है। दूध तो गाय का सबसे सस्ता उत्पाद है किन्तु गोबर और गौ-मूत्र बहुमूल्य उत्पाद या कीमती पदार्थ हैं। गाय का दूध तो मानव के लिये पौष्टिक आहार है किन्तु उससे भी अधिक गौ-वंश का गोबर और गोमूत्र धरती का पोषण आहार है। मानव शरीर और मानवीय बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिये दूध, दही, मही, घी, मक्खन और धरती को स्वस्थ और उर्वरक बनाये रखने के लिये गोबर, गौ-मूत्र धरती का पारम्परिक आहार है। मनुष्य की भाँति धरती को भी पोषण आहार की आवश्यकता है उसकी पूर्ति गौ-वंश से प्राप्त गोबर और गौ-मूत्र से होती है। इतना ही नहीं गोबर और गौ-मूत्र से अनेक उत्पाद आज वैज्ञानिक पद्धति से तैयार हो रहे हैं।

हैं। हम गौ-शालाओं से प्राप्त गोबर के अनेक उत्पादों यथा गोबर के दीपक, गमले, पेंट, गौ-मूत्र से बनाये गये गोनाईल आदि के विक्रय से आर्थिक लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार होलिका दहन भी गोबर से बने कण्डों से तथा गौ-काष्ठ से करने का प्रचलन आरम्भ कर, जंगल से लकड़ी काटने में रोक लगा कर पर्यावरण का संरक्षण करने का अभियान चला सकते हैं। जंगल कटने से बचेंगे और पर्यावरण सुरक्षित होगा।

दीपावली और होलिकोत्सव से यदि हम गौ-वंश को जोड़ कर उसका विश्लेषण युगानुकूल, सामयिक और नवाचार के साथ करें तो गौ-शालाओं में आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भरता और स्वावलम्बन के द्वार खोले जा सकते हैं।

भारतवर्ष के सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दीपावली और उसके आस-पास की तिथियाँ आर्थिक समृद्धि की देवी लक्ष्मी के पर्व की तिथियाँ

मानव की मृत देह का अंतिम संस्कार भी गौ-शालाओं में गोबर से बनने वाले गौ-काष्ठ और गोबर के कण्डों से कर सकते हैं। इस विधि से भी गौ-शालाओं में आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

लेखक मध्यप्रदेश गौ-संरक्षण एवं संवर्द्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष है।

प्रत्येक मतदाता को नमन

25 जनवरी के दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, जिसे वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) के रूप में भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को मतदाता के रूप में उनके अधिकारों और दायित्वों से अवगत कराना है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की स्थापना प्रथम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानि 25 जनवरी, 1950 को हुई थी। संविधान सभा ने आयोग को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया ताकि यह अपने कामकाज में और निर्णय लेने में स्वतंत्र रूप से काम कर सके। अल्प साक्षरता और निर्वाचक नामावली की गैर-मौजूदगी वाले दौर में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों का संचालन करने के लिए एक स्थायी, केन्द्रीय और स्वायत्त आयोग की स्थापना करना संविधान सभा की दूरदर्शिता को दर्शाता है। इस संस्था की सक्षमता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता अब तक संचालित 17 लोकसभा चुनावों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के 16 चुनावों, 399 विधान सभा चुनावों से परिलक्षित होती है। 400वें विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। कभी-कभार के अंतरराष्ट्रीय अनुभव के उलट,भारत में निर्वाचन परिणामों को लेकर कभी भी विवाद नहीं रहा है। चुनाव परिणाम संबंधी याचिकाओं पर संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा चुनाव याचिका दिए जाने पर फैसले देने का प्रावधान है। आयोग ने भारत के राजनीतिक दलों और नागरिक दोनों का भरोसा हासिल किया है। इस भरोसे को बढ़ाना और पुख़्ताकरना आयोग का संकल्प है।

एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए पुरजोर और सर्वसमावेशी चुनावी भागीदारी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस चुनावों को और अधिक समावेशी, सहभागी और मतदाता-हितैषी बनाने के आयोग के प्रयासों को अभिव्यक्त करता है। एक जीवंत लोकतंत्र में चुनावों का स्वतंत्र, निष्पक्ष, नियमित और विश्वसनीय होना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें सर्वप्रिय होने के साथ-साथ सहभागी होना चाहिए ताकि शासन व्यवस्था पर उनका पूर्ण प्रभाव दिखे। वोट करने का अधिकार शक्ति के रूप में केवल

तभी परिणत होगा जबकि उसका प्रयोग किया जाए। हमें महात्मा गांधी की एक उक्ति याद आती है- यदि कर्तव्यों का पालन न करके हम अधिकारों के पीछे भागते हैं, तो वे अलभ्य वस्तु की भांति हमारी पकड़ से निकल जाते हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां 94 करोड़ से अधिक पंजीकृत निर्वाचक हैं। फिर भी, पिछले आम चुनावों (2019) में 67.4 प्रतिशत के वास्तविक मतदान आंकड़े बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश रखते हैं। चुनौती यह है कि बूथ तक न पहुंच सकने वाले 30 करोड़ निर्वाचकों को कैसे प्रेरित किया जाए। बूथ से दूररहने वालेमतदाताओं के कई कारण हैं जैसे कि शहरी उदासीनता, युवा उदासीनता, घरेलू प्रवासनइत्यादि। जैसा कि अधिकांश उदार लोकतंत्र,जहां पंजीकरण और मतदान स्वैच्छिक हैं,में भी प्रचलित है, मतदाता कोप्रेरित कर और अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर मतदान केन्द्र पर लाना ही श्रेयस्कर रणनीति है। यह कम मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों और कम मतदान करने वाले समूहों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत उत्पन्न करता है।

आयोग ने अस्सी वर्ष और उससे अधिक आयु के दो करोड़ से अधिक मतदाताओं, पचासी लाख पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए, 47500 से अधिक थर्ड जेंडर व्यक्तियों को पंजीकृत करने के लिएपहले से विद्यमान तंत्र को संस्थागत स्वरूप प्रदान कर दिया है। हाल में, दो लाख से अधिक शतायु मतदाताओं को, लोकतंत्र के प्रति

उनकीप्रतिबद्धता को मान्यता देने के लिए व्यक्तिगत पत्र भेजकर उन सबका शुक्रिया अदा किया गया। 5 नवंबर, 2022 को मैंने हिमाचल प्रदेश के कल्पा में दिवंगत श्री श्याम सरन नेगी को श्रद्धांजलि देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भारत के पहले आम चुनाव (1951) में प्रथम मतदाता के रूप में पंजीकृत श्री नेगी 106 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा लेने से पहले, वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से कभी नहीं चूके। स्वर्गीय श्याम सरन नेगी जी का उदाहरण हमें कर्तव्यनिष्ठा के साथ मतदान करने के लिए प्रेरित करता है।

युवा मतदाता भारतीय लोकतंत्र के भविष्य हैं। वर्ष 2000 के आसपास और उसके बाद पैदा हुई पीढ़ी ने हमारी निर्वाचक नामावली में शामिल होना शुरू कर दिया है। मतदाताओं के रूप में उनकी भागीदारी लगभग पूरी सदी के दौरान लोकतंत्र के भविष्य को आकार देगी। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि छात्र मतदान करने की आयु तक पहुंचें, उससे पहले विद्यालय स्तर पर ही उनमें लोकतंत्र की जड़ों का बीजारोपण कर दिया जाए। साथ ही साथ, युवा लोगों को विभिन्न माध्यमों के जरिए जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें पोलिंग बूथों तक लाया जा सके।यही हाल शहरी मतदाताओं का भी है जिनमें मतदान के प्रति उदासीनता देखने को मिल रही है।

भारत निर्वाचन आयोग हर मतदान केंद्र पर शौचालय, बिजली, पेयजल, रैंप जैसी आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) प्रदान करने के काम में लगा हुआ है। आयोगइस बात को लेकर गंभीर है कि स्कूलों में तैयार की जा रही सुविधाएं स्थायी स्वरूप की होनी चाहिए जोवित्तीय रूप से भी संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए आवश्यक है।

लोकतंत्र में, मतदाताओं को इस बात का अधिकार है कि वेउन उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानें, वे जिन्हें वोट देते हैं। इस तरह मतदाता को informed विकल्प चुनने में समर्थ बनाना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि उम्मीदवारों के खिलाफ यदि कोई आपराधिक मामला लंबित है तो उसकी सूचना समाचार पत्रों में दी जानी चाहिए। इसी तरह, जहां हर राजनीतिक दल को अपने घोषणापत्र में कल्याणकारी उपायों का वादा करने का अधिकार है, वहीं मतदाताओं को भी उससे राजकोष पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव कोजानने का समान रूप से अधिकार है।

हालांकि, बाहुबल पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया गया है, फिर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां चुनावी हिंसा मतदाता के स्वतंत्र विकल्प में बाधा डालतीहै। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। चुनावों में धनशक्ति पर लगाम लगाना कहीं अधिक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मतदाताओं को पेश किए जा रहे लालच एवं प्रलोभन की व्यापकता और मात्रा,

खासकर कुछ राज्यों में अधिक गंभीरतापूर्वक महसूस की जा रही है। हालांकि, कानून लागू कराने वाली एजेंसियों द्वारा कड़ी निगरानी के परिणामस्वरूप हाल ही में आयोजित हुए चुनावों के दौरान रिकॉर्ड बरामदगी देखने को मिली है, फिर भी लोकतंत्र में निष्ठावान और सतर्क मतदाता ही दुरुपयोग को रोकने में भागीदारी कर सकते हैं। सी-विजिल जैसे मोबाइल ऐप से आम नागरिक को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं की सूचना देने में मदद मिली है, जिससे निर्वाचन प्रेक्षकों को गलती करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई (100 मिनट के भीतर) शुरू करने में मदद मिली है।

विश्वसनीय चुनावी परिणामों के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बरकरार रखना तथा उन्हें और सशक्त बनाना दुनिया भर में प्राथमिकता बना हुआ है। जिस पैमाने और गति से सोशल मीडिया तथ्यों और विचारों/फर्जी समाचारों का प्रसार कर सकता है, उससे चुनाव प्रबंधन में टेक्नोलॉजी की अन्य पहलुएं बेअसर हो सकती हैं। (नैतिक और कानूनी व्यवस्थाओं के आधार, जो आयोग की भूमिका और फ्रेमवर्क को शासित करते हैं - से मुक्त लोकतंत्र विरोधी तर्क-वितर्क टेक्नोलॉजी को अपने पेशे के एक कारगर हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है।)

हर चुनाव से पहले सैकड़ों फर्जी मीडिया वीडियो/सामग्री लोड और प्रसारित की जाती हैं। शेल्फ-लाइफ के अभाव में, वे चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भी डिजिटल स्पेस में बने रहते हैं, विशेष रूप से ऐसी सामग्री जिनमें प्रमुख निर्वाचन प्रक्रियाओं पर प्रहार किया गया हो। दुनिया भर में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मो से इतनी उम्मीद की जा रही है कि वे इस तरह के प्रत्यक्ष दुष्प्रचार प्रयासों के प्रति सचेत और जागरूक करने के लिए अपनी व्यापकएआई क्षमताओं का ज़रूर इस्तेमाल करें। अभिव्यक्ति की आजादी सहित स्वतंत्र संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व हम सबका है। यह स्वीकार करना कि अत्यन्त फर्जी समाचारों से चुनाव प्रबंधन निकायों का काम और अधिक मुश्किल हो जाता है, यह सबको समझना चाहिए और आत्म-सुधार करना चाहिए।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस चुनावों को समावेशी, सहभागी, मतदाता-हितैषी और नीतिपरक बनाने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के आयोगके संकल्प को प्रतिबिंबित करता है। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस(2023) की थीम वोटजैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम है। यह थीम मतदाताओं की कल्पना में रच-बस सकती है। जब नागरिक अपने नागरिक दायित्व के रूप में मतदाता होने पर गर्व महसूस करेंगे, तो शासन के स्तर पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से महसूस किया जाएगा।

लेखक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं

देश की सियासत में चमकते चेहरा बने योगी आदित्यनाथ

मणिशंकर पाण्डे

पिछले सात साल में उत्तरप्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कद दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। हिन्दुत्व की राह पर चलते हुए योगी ने अपने प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में एक अलग ही छबि बना ली है। योगी का कद इतना बढ़ गया है कि राजनीतिक विश्लेषक उन्हें मोदी का उत्तराधिकारी मानने लगे हैं। हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री का दावेदार माना जाने लगे। यूपी की राजनीति ने देश की राजनीति का रुख तय किया है। मुद्दे दिए हैं। दिल्ली की कुर्सी तय की है। प्रधानमंत्री दिए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी ही तीसरी बार जीत के लिए भाजपा का रामबाण बन सकता है। योगी आदित्यनाथ की हिन्दुत्व और विकास के मॉडल वाली छवि राष्ट्रीय ख्याति हासिल कर रही है। भाजपा के लिए योगी का चेहरा और लोकप्रियता लोकसभा चुनाव जीतने का रामबाण बन सकता है। उतरप्रदेश में योगी ने जिस तरह माफियाओं, गुण्डों पर कार्यवाही की है उससे उनकी छबि एक सशक्त और निडर राजनेता की बन गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ता जा रहा है। उनका सख्त एक्शन, भाषण, गवर्नेंस और सियासत भाजपा की ताकत बढ़ा रही है। केंद्र की राजनीति की दिशा और दिल्ली की कुर्सी तय करने वाले सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक परिपक्वता निखर रही है।

सरकार चलाने की कठोर नीति, विकास और उपलब्धियों के गुणों के बखान वाला योगी का धुआंधार भाषण आम और ख़ास चर्चाओं में भी रहता है और सुर्खियों में भी। योगी लम्बे समय तक गोरखपुर से सांसद रहे, अच्छे वक्ता और पुराने राजनेता हैं। यूपी सहित पूरे देश की राजनीति से उनका पुराना रिश्ता रहा किंतु यूपी में मुख्यमंत्री बनने के बाद ना सिर्फ सख्त नीतियों वाली गुड गवर्नेस से बल्कि योगी की राजनीतिक सूझबूझ और धारदार भाषणों से भी उनका सियासी क़द बढ़ रहा है। सदन हो या चुनावी मंच हों, उनके धुआंधार भाषण, विकास और हिंदुत्व की छवि से बढ़ती उनकी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को तरक्की की सीढ़ियां बनकर ऊंचाइयों पर लिए जा रही है। योगी ने शपथ ग्रहण करते ही यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने की बात कही। 2017 से 2022 तक योगी ने माफियाओं, बदमाशों, हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर बुलडोजर चले। 2022 यूपी चुनाव की

योगी ने शपथ ग्रहण करते ही यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने की बात कही। 2017 से 2022 तक योगी ने माफियाओं, बदमाशों, हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर बुलडोजर चले। 2022 यूपी चुनाव की घोषणा से काफी पहले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार में लग गए थे। धीरे-धीरे बाबा का बुलडोजर एक ब्रांड बनने लगा। चुनाव में भी यूपी की मजबूरी है बुलडोजर बाबा जरूरी है के नारे लगाए गए।

घोषणा से काफी पहले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार में लग गए थे। धीरे-धीरे बाबा का बुलडोजर एक ब्रांड बनने लगा। चुनाव में भी यूपी की मजबूरी है बुलडोजर बाबा जरूरी है के नारे लगाए गए। पोस्टर, बैनर, सभाएं हर जगह योगी के साथ बुलडोजर नजर आने लगा। योगी के बुलडोजर का प्रचार सिर्फ यूपी तक नहीं, बल्कि देश के बाकी रायों तक होने लगा। बाकी राज्यों में भी लोग अपराध को खत्म करने के लिए योगी के बुलडोजर पैटर्न को लागू करने की मांग करने लगे। इसका असर यूपी के चुनाव में देखने को मिला। भाजपा ने 2022 में भी 403 में से 273 सीटों पर जीत हासिल कर दोबारा सरकार बना ली। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम बने। सीएम योगी आज एक नए अवतार में दिखने लगे हैं। अपनी पूर्व की छवियों से आगे निकलकर योगी अब एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं जो अनुशासित और निर्णायक होने के साथ-साथ समावेशी भी दिख रहे हैं और केवल एक पहचान के दायरे से बाहर भी अपने लिए लोकप्रियता का समाज गढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लेकिन इन पांच

वर्षो के दौरान और उसके बाद भी योगी की छवि का जो सबसे पहला भाव है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और वो भाव है भगवावस्त्र पहनने वाले एक हिंदुत्ववादी नेता का जिसके सोचने-समझने की शैली का केंद्रीय भाव हिंदू और हिंदुत्व ही है। योगी इसको बदलना भी नहीं चाहते और न बदल सकते हैं। उन्हें शायद कुछ बदलकर बड़े होने की ज़रूरत भी नहीं है। उन्हें पूर्ण अर्जित छवि में और जोड़ने की ज़रूरत है और वो काम योगी शुरू कर चुके हैं।

अतीक अहमद वाले मामले में तो योगी आई योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कोई मुरव्वत नहीं करते हुए उनके एनकाउंटर करने पर अधिक जोर दिया। मेर में चोरी के वाहनों को काटकर बेचने वाले बाजार पर शिंकजा कसा। बाजार चला रहे 31 से यादा माफिया की 40 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, अतीक अहमद जैसे माफिया व अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1800 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। दावा किया गया कि इससे प्रदेश का माहौल बेहतर हुआ और निवेश लिए चलाए गए एंटी रोमियो स्क्वॉयड अभियान के चलते भी महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी देखी गई है। उत्तरप्रदेश में जो घटना हुई है उससे पूरे देश में सियासी पारा गरम है। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके सरकारी गनर की प्रयागराज में हुई हत्या के मामले से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्माने का मौका दे दिया हैं। यह हत्याकांड से पूरा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा है। इसमें मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जब घोषणा की है कि माफियाओं को मिट्टी में

आदित्यनाथ की छबि को और स्पष्ट कर दिया है। बड़ी संख्या में लोगों ने माफियाराज खत्म करने के इस तरीके को सही ठहराते हुए सीएम योगी की तारीफ की है, तो कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। बुलडोजर और एनकाउंटर की राजनीति क्या है? इसने योगी आदित्यनाथ की छवि कैसे चमकाई है? विपक्ष क्यों इस नीति पर सवाल उठाता है? अखिलेश सरकार में अपराधों की स्थिति और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाकर सत्ता में बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा हुए।

वैसे तो उत्तरप्रदेश में कानून-व्यवस्था के लिए लोग बसपा सुप्रीमो मायावती के शासन को याद करते हैं। मायावती की छवि सख्त प्रशासक की थी। माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ वे अपनों पर भी कार्रवाई करने में नहीं हिचकती थीं। मगर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने माफिया और अपराधियों में खौफ पैदा किया है। बेटियों की सुरक्षा के मिला देंगे। उन्होंने जब ये कहा है, उसके दो दिन बाद ही अतीक अहमद के पुराने साथी अरबाज को पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर में गिरा दिया है और उसकी मौत हो गई। हाल ही में अतीक अहमद और उसके भाई की भी प्रयागराज में हत्या कर दी गई। इस मामले ने देश भर में काफी तूल पकड़ा है। चूंकि अतीक अहमद का पुराना आपराधिक इतिहास है। उस पर सौ से अधिक मुकदमें दर्ज थे। जब जनवरी 2005 में राजूपाल की हत्या कर दी गई थी। उसमें

ये सामने आया था कि अतीक के भाई अशरफ सीधे-सीधे वारदात में शामिल थे और वह भी घटनास्थल पर मौजूद थे। उमेश पाल उसी हत्याकांड के गवाह थे। राजूपाल पहले अतीक अहमद के साथ ही था। 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो अतीक अहमद फूलपर चले गए सांसद का चुनाव लड़ने। उस वक्त अतीक अमहद प्रयागराज की जो पश्चिम विधानसभा सीट है, उसके विधायक थे। 2005 में फूलपुर से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। उसके बाद प्रयागराज पश्चिम की विधानसभा सीट खाली हो गई। उन्होंने वहां से अपने भाई अशरफ को लड़ाने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त राजूपाल ने भी वहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और बीएसपी ने उनको टिकट दे दिया। और वो जीत भी गए और अशरफ चुनाव हार गए। धीरे-धीरे ये पॉलिटिकल दुश्मनी व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल गई और 25 जनवरी 2005 में जब राजूपाल एसआरएम हॉस्पिटल कॉलेज गाड़ी से जा रहे थे, तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनको ओवरटेक किया और उन पर हमला कर दिया। उनकी हत्या कर दी गई। ये कहा जाता है कि उमेश पाल उस वक्त उस घटना के चश्मदीद थे। और वही इस मामले की पैरवी कर रहे थे। इस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, जो उमेश पाल की हत्या हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि उमेश पाल किसी भी सूरत में अपनी गवाही से पीछे नहीं हट रहे थे। और दूसरे केसेस में भी उन्होंने पैरवी करना शुरू कर दिया था। ये उमेश पाल की हत्या की मुख्य वजह रही।

प्रयागराज की वारदात योगी सरकार को घेरने का बड़ा मौका थी। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा भी। कोई और मुख्यमंत्री होता तो शायद नर्वस हो जाता, तनाव में आ जाता। किंतु मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने विवेक से काम लिया। तर्को और तथ्यों के साथ विपक्ष को उसकी ही पिच पर धूल चटा दी। मुख्यमंत्री ने सपा को याद दिलाया कि प्रयागराज के कथित मास्टरमाइंड अतीक अहमद की राजनीतिक संरक्षक सपा ही है। बिना वक्त गंवाए मुख्यमंत्री ने एक वाक्य मट्टी में मिला देंगे के ज़रिए ना सिर्फ विपक्ष को जवाब दिया बल्कि सदन से ही अपने प्रशासनिक-पुलिसिया तंत्र को भी तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए। योगी के यही फैसले हैं जो उन्हें निडर और साहसी नेता बनाता है।

एनकाउंटर के आंकड़े

यूपी में 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर खूब सवाल खड़े किए जाते थे। लूट-छिनैती, मर्डर, रेप जैसी घटनाओं पर अखिलेश सरकार लगभग हर दिन घिरी रहती थी। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से यूपी की छवि बदलने की कोशिश शुरू हो गई। कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए जहां एक तरफ सीएम योगी ने बुलडोजर चलवाए, वहीं दूसरी ओर माफियाओं और बदमाशों का एनकाउंटर भी होने लगा। यूपी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से अब तक कुल 10,720 एनकाउंटर हो चुके हैं। इनमें अतीक अहमद के बेटे असद अहमद, उसके गुर्गे गुलाम, अरबाज और उस्मान चौधरी भी शामिल हैं। इसके अलावा कानपुर में पुलिस टीम पर गोलियां बरसाने वाले कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गुर्गो के नाम भी शामिल हैं। अगर पिछले छह साल की बात करें तो बीते वर्ष पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ का आंकड़ा सबसे कम रहा है। वर्ष 2018 में सर्वाधिक 41 अपराधी मारे गए थे। इससे पहले साल 2017 में 28, साल 2019 में 34, साल 2020 में 26, साल 2021 में 26 व पिछले वर्ष 2022 में 14 अपराधी मारे गए हैं। साल 2023 में अब तक 11 बदमाश मारे गए हैं। बीते छह वर्ष में पुलिस मुठभेड़ में 23 हजार से यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर के दौरान 12 पुलिसकर्मी शहीद और 1400 घायल हुए

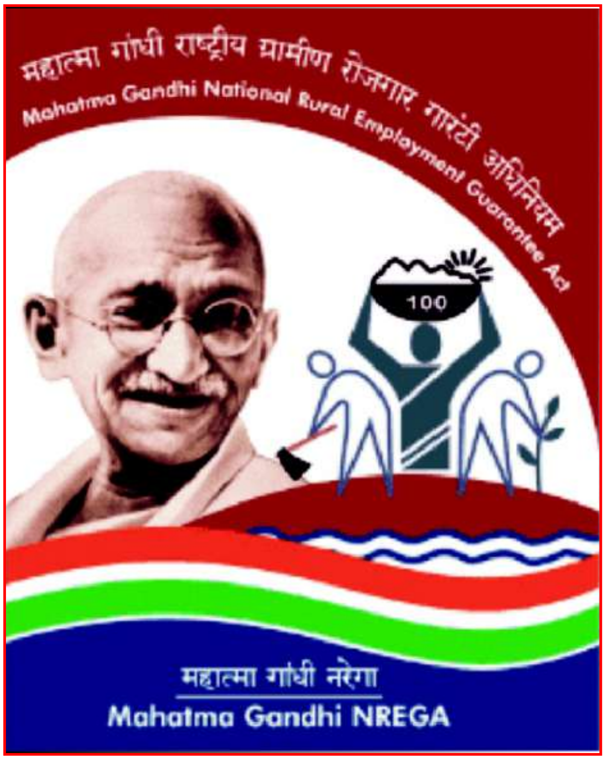

मनरेगा की जड़ें रामराज्य में हैं

रघु ठाकुर

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के भविष्य को लेकर देश में एक बार चर्चा फिर शुरू हुई है। यह योजना मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू हुई थी परन्तु कहा जाता है कि वे इसे लागू करने के पक्षधर नहीं थे। विश्व बैंक से प्रभावित उनका मस्तिष्क और विचार ऐसी योजनाओं के पक्ष में नहीं हो सकते थे जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनकी मशीनों की भूमिका न हो परन्तु यह एक प्रकार से उनकी अंतर्दलीय विवशता ही थी कि सारे प्रयास के बाद भी उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा था। वैसे तो भूख से बचाने और हर नागरिक को रोटी और रोजगार उपलब्ध कराने का दायित्व राजा का है। यह उपदेश भगवान राम ने भी दिया था। जब वे वनवास पर थे तथा उनके अनुज भरत जो अयोध्या के शासक थे, जब उनसे मिलने के लिये वन में गये तो राम ने उनसे जो प्रश्न पूछे थे वह प्रश्न मात्र नहीं थे, बल्कि नीति के सूत्र और निर्देश थे। राम भरत संवाद रामायण में वर्णित है। जिसमें वह भरत से पूछते है कि राज्य में कोई भूखा तो नहीं सोता। राय में कोई दुखी तो नहीं है। और ऐसे ही अनेकों प्रश्न पूछकर श्रीराम ने नीति के सूत्र दिये थे। दरअसल मनरेगा भगवान राम के संदेश या अंर्तनिहित निर्देश से निकली एक योजना थी। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, ग्रामीण क्षेत्र में उसे कोई न कोई रोजगार मिले ताकि वह भूख से मुक्त हो और जीवन यापन कर सके।

मनरेगा कानून संसद में आने के बाद पहली बार में पारित नहीं हो सका था और उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का निर्णय हुआ था। यह एक सुविदित तथ्य है। जब किसी विषय पर सरकार निर्णय नहीं करना चाहती और बगैर दोष लिये उसे विलम्बित करना चाहती है, तो ऐसे प्रस्ताव संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिये जाते हैं।

मनरेगा कानून संसद में आने के बाद पहली बार में पारित नहीं हो सका था और उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का निर्णय हुआ था। यह एक सुविदित तथ्य है। जब किसी विषय पर सरकार निर्णय नहीं करना चाहती और बगैर दोष लिये उसे विलम्बित करना चाहती है, तो ऐसे प्रस्ताव संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिये जाते हैं। यही घटना मनरेगा के प्रस्ताव पर हुई थी कि संसद में मनरेगा के कानून पेश होने के बाद कोइ निर्णय नहीं हो सका और उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। जिस समिति को भेजा गया था उसके अध्यक्ष स्व. कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री

उ.प्र. थे और ऐसा प्रतीत होता है कि वे और जो कुछ भी हो पर भगवान राम के नाम के प्रति समर्पित थे। उन्होंने तो अयोध्या में जाने के लिये अपनी सरकार को भी दांव पर लगा दिया था और राम मंदिर निर्माण की भूमिका रखी थी। जब उन्हें समिति के किसी सदस्य ने राम भरत संदेश का प्रसंग सुनाकर प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये कहा तब उन्होंने तत्काल साहस के साथ समर्थन किया। यद्यपि उनकी पार्टी की भी विपक्ष की अध्यक्षता वाली समिति ने ही प्रस्ताव का समर्थन कर दिया तो प्रधानमंत्री के पास इसे पारित करने और लागू कराने के अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं था। मनरेगा लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर करोड़ों ग्रामीण मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले और पहले जो गाँव में भूख से मरने के समाचार अक्सर छपते थे, वह काफी हद तक बंद या कम हो गये। मनरेगा जब विमर्श के राष्ट्रीय फलक पर चाणक्य के निर्देश में यह संदेश भी निहित रहा होगा कि प्रजा अगर काम में मशगूल रहेगी और भुखमरी नहीं होगी तो राजा के खिलाफ विरोध या बगावत नहीं होगी। डॉ. अशोक पंकज ने कई रायों के मनरेगा के कार्यमों का अध्ययन कर कुछ ठोस निष्कर्ष निकाले हैं। मनरेगा के बारे में एक आरोप आमतौर पर यह लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार होता है। इस आरोप को नकारा नहीं जा सकता परन्तु यह भी उल्लेखनीय है

आम राय इसके पक्ष में नहीं थी। बहुत सम्भव है इसका कारण यह रहा हो कि उनकी पार्टी भाजपा को यह लगता था की मनरेगा कानून बनने के बाद गाँव में मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, और यह कानून कांग्रेस की सरकार में वापिसी के लिये लाभदायक होगा, क्योंकि इस कानून के अनुसार मजदूरों को उनके ग्राम या समीपी क्षेत्र में ही रोजगार देने की अनिवार्यता थी। इसके बावजूद स्व. कल्याण सिंह ने संयुक्त संसदीय समिति में मनरेगा का न केवल समर्थन किया, बल्कि उसे मजबूती के साथ पास कराया और जब प्रमुख है तब यह भी सुखद संयोग है कि इसी समय डॉ. अशोक पंकज जी की पुस्तक इन क्लूजिव डेवलपमेंट गारंटीड एम्पालायेमेंट प्रकाशित हुई है। जिसे स्प्रिंगर ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में डॉ. पंकज ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को उद्धत करते हुए लिखा है कि चाणक्य ने राजा को सलाह दी थी कि प्रजा की खुशी में राजा की खुशी रहती है। प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण निहित रहता है, इसीलिये दुर्गा (किलो) का निर्माण करो, सिंचाई को नहरें आदि बनाओ ताकि प्रजा को काम मिल सके और वह सुखी रह सके। शायद कि भ्रष्टाचार नीति या योजना का नहीं है, बल्कि यिान्वयन करने वाली संस्थाओं या एंजेंसियों का है, और जिसे प्रशासनिक कसावट से काफी हद तक दूर किया जा सकता है। दूसरा आक्षेप यह लगता है कि मनरेगा के काम जिन्हें कानून के अनुसार श्रमिक के हाथों से होना चाहिए उन्हें मशीनों द्वारा कराया जाता है। क्योंकि श्रमिक नहीं मिलते।

मैं मानता हूं कि दो कारण से विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या पर प्रभाव पड़ा है। एक तो इसलिये की अब पुरानी सामाजिक संरचनायें टूट रही है। और गाँव

का मजदूर जो बाहर जाकर तो मजदूरी व कठोर से कठोर श्रम करने को तैयार रहता है, परन्तु अपने गाँव में वह कुछ सामाजिक कारण से उसे असम्मान जनक महसूस करता है। दूसरा इससे भी बड़ा कारण है कि जब गाँव का मजदूर काम के लिये बाहर जाता है तो उसे मजदूरी में यादा पैसा मिलता है। दिल्ली में ग्रामीण मजदूर को 400-500 सौ रूपये रोज मिल जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मार पीट और हमले की जो बर्बर घटना मीडिया में आई है अगर वह सही है निसंदेह वह प्रशासनिक मशीनरी की विशेषतः कानून व्यवस्था लागू करने वाली पुलिस की असफलता है। यद्यपि मजदूरों को पीटते हुए जो वीडियो वायरल हुए है, उनका तमिलनाडु के डी.जी. पुलिस ने यह कहकर खण्डन किया है कि यह गलत वीडिया डाले गये हैं, जो पुराने छात्रों के आपसी झगड़े के हैं। हालांकि बिहार के कुछ मजदूरों के परिजनों ने तो अपने परिजन श्रमिकों से बात कर बताया है कि उनके परिजनों के साथ हिंसात्मक घटनाएं घटी है, और हो रही है। निसंदेह यह एक गंभीर मामला है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच सी.बी.आई. या न्यायिक संस्था द्वारा होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

दिल्ली में ग्रामीण मजदूर को 400-500 सौ रूपये रोज मिल जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मार पीट और हमले की जो बर्बर घटना मीडिया में आई है अगर वह सही है निसंदेह वह प्रशासनिक मशीनरी की विशेषतः कानून व्यवस्था लागू करने वाली पुलिस की असफलता है।

परन्तु इस हिंसा का जो कारण बताया गया है, अगर वह सच है तो वह महत्वपूर्ण है। बिहार के मजदूरों का कहना है कि स्थानीय मजदूर उन्हें इसलिये भगाना चाहते हैं क्योंकि वे वही काम सात सौ से आठ सौ रूपये रोज में कर रहे हैं जिसके लिये तमिल श्रमिक 1200 रूपया रोज लेते थे। अब चूंकि मालिकों के लिये बिहार का श्रमिक सस्ता है, चार पांच सौ रूपया कम पर उपलब्ध है, वे तमिल श्रमिकों के बजाय बिहार के श्रमिकों को प्राथमिकता देते है, जो कि स्वाभाविक भी है। चूंकि मनरेगा की मजदूरी लगभग ढाई सौ रूपया रोज है, अतः बिहार का व्यक्ति तमिलनाडु पंजाब या दिल्ली आदि शहरों में जाकर काम करना पसंद करता है। क्योंकि उसे वहां तीन से चार गुना मजदूरी मिल रही है। मनरेगा में श्रमिकों की कमी की बड़ी वजह कम मजदूरी भी है और जब श्रमिक नहीं मिलते

है तो अपने निर्धारित ग्रामीण और स्थानीय कार्यो को पूरा कराने के लिये अधिकारी लाचार होकर मशीनों का प्रयोग कराते हैं ताकि वह अनुशासनात्मक कार्यवाही से बच सकें। अगर भारत सरकार समूचे देश के श्रमिकों के लिये चाहे वह शासकीय हो या अशासकीय हो एक समान मजदूर की दर तय करे तो स्थानीय श्रमिकों के अभाव की समस्या का काफी हद तक हल निकल जायेगा।

एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ग्रामीण अंचल में निशुल्क राशन पांच किलो प्रति व्यक्ति की दर से वितरण शुरू हुआ है। निसंदेह इससे गरीबों को भूख से बचने की गारन्टी मिली है और सरकार को भी चुनाव जीतने की गारंटी। परन्तु अनुभव यह भी आ रहा है कि देश में बगैर परिश्रम के खाने वालों की एक बड़ी फौज तैयार हो रही है जो धीरे-धीरे अकर्मण्य बनती जा रही है। और जब मुफ्त राशन से ही जीवन चल जाये तो व्यक्ति को श्रम करने की क्या आवश्यकता है यह सोच मजदूरों का बन रहा है। हमारे बुंदेलखण्ड में एक पुरानी कहावत चलती है कि जब बैठ के मिले खाने, तो कौन जाय कमाने। मनरेगा इस अर्थ में मुफ्त राशन वितरण से बेहतर योजना है। जिसमें श्रम के बदले रोजगार है और स्थानीय स्तर पर घर के नजदीक रोजगार की गारंटी है। अगर नीचे लिखित संशोधन कानून में कर दिये जाये तो दोनों प्रकार की समस्या का बेहतर निराकरण हो सकता है।

1.देश में समान मजदूरी दर,

2.निशुल्क या मुफ्त राशन बीमारों वृद्धों विकलांगों व केवल उनके लिये जिन्हें सरकार कोई काम नहीं दे पाती ही दिया जाये।

निःशुल्क राशन वितरण की वजह से जो आर्थिक बोझ सरकार पर आ रहा है। शायद उससे मुक्ति पाने के लिये सरकार ने मनरेगा का बजट कम करना शुरू कर

दिया है। वर्ष 2022-23 के बजट में मनरेगा को 89 हज़ार करोड़ राशि रखी थी। जिसे 2023-24 में घटाकर 60 हज़ार करोड़ कर दिया गया। याने लगभग 30 हज़ार करोड़ की बजट राशि कम कर दी गई। वर्ष 2022-23 के 12 हज़ार करोड़ की मजदूरी की बकाया देनदारी और 6 हज़ार एक सौ करोड़ की सामग्री की देनदारी भी बकाया है जिसे नये बजट में चुकाना होगा। याने की 18 हज़ार करोड़ की पिछली देनदारी इस नये सत्र के बजट से होगी। इसका अर्थ हुआ कि इस वर्ष वास्तविक वार्षिक बजट लगभग 42 हज़ार करोड़ रूपया ही होगा जो पिछले बजट की तुलना में लगभग आधे से भी कम होगा। देश के प्रबुद्ध तबके में यह संदेह है कि भारत सरकार इस प्रकार क्रमशः मनरेगा के बजट को कम कर मनरेगा की योजना को समाप्त करना चाहती है। कुछ लोगों का यह भी आक्षेप है कि सरकार मनरेगा को कांग्रेस सरकार की योजना मानती है और इसलिये इसे समाप्त करना चाहती है। जबकि मनरेगा को तो भगवान राम का संदेश मानकर स्वर्गीय कल्याण सिंह ने पारित कराया था अन्यथा यह पारित नहीं हो सकता था।

मनरेगा में स्थायी कार्यो का हिस्सा बढ़ाने के लिये इसे रेल लाईनों के विस्तार और नदी जोड़ो योजना के साथ भी जोड़ा जा सकता है। यह और भी उपयोगी होगा। जिसमें, भ्रष्टाचार भी कम होगा तथा व्यय का परिणाम स्थायी विकास और रोजगार के रूप में मिलेगा। मनरेगा की राशि को फिजूल खर्ची से बचाया जाना चाहिए। आजकल नया चलन शुरू हुआ है कि मनरेगा की राशि से सरकारे बड़े-बड़े विज्ञापन जारी करती है जबकि मनरेगा प्रचार नहीं विचार की योजना है। मनरेगा विज्ञापन की नहीं हर श्रमिक को स्थानीय तौर पर रोजगार संरक्षण की योजना है। यह आश्चर्यजनक है कि मंदिरों में पाषाण प्रतिमाओं की स्थापना में हजारों करोड़ रूपया सरकारी खर्च हो रहा है जबकि ईश्वर की सबसे सुन्दर कृति मनुष्य के लिये बजट कम हो रहा है। मैं भारत सरकार और राय सरकारों से उम्मीद करूंगा की वह उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अपनी नीति को पुनः संशोधित करें। डॉ. अशोक पंकज की पुस्तक जो मनरेगा कानून उसके यिान्वयन उसके वर्तमान और भविष्य का निष्पक्ष और बेबाक चिन्तन करती है, इस उद्देश्य के लिये बहुत ही उपयोगी है। उनकी पुस्तक को पढ़कर मुझे भी कई नये तथ्य और जानकारीयां मिली हैं। डॉ. अशोक पंकज को इसके लिये साधुवाद।

जनसंख्या वृद्धि खुशी के साथ चिंता भी !

प्रमोद भार्गव

भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जहां दुविधाएं और विरोधाभास प्रगति के समानान्तर चलते हैं। अतएव जनसंख्या बल जहां शक्ति का प्रतीक है, वहीं उपलब्ध संसाधनों पर बोझ भी है। इसलिए अनेक समस्याएं भी सुरसामुख बन खड़ी होती रहती हैं। ये हालात तब और कठिन हो जाते हैं, जब संसाधनों के बटवारे में विसंगति बढ़ती चली जा रही हो? गोया कहा जा सकता है कि बढ़ती आबादी वरदान नहीं बोझ है। नतीजतन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट ने जब ये आंकड़े जारी किए कि भारत की आबादी चीन से अधिक बढ़ गई है, तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि यह संभावना बहुत पहले से जताई जा रही थी कि भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। वाबजूद कुछ जनसंख्या विशेषज्ञ इस बात को लेकर शंका जता रहे हैं कि यह समय अभी नहीं जून में आना था।परंतु आम आदमी को आंकड़ों की बाजीगरी न तो आसानी से समझ आती है और न ही वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता है। अतएव चीन के इस बयान पर गौर करने की जरूरत है कि वह आंकड़े आने के बाद आखिर यह क्यों कह रहा है कि अभी भी उसके पास 90 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं,जो कुशल उत्पादन की क्षमता रखते हैं। याद रहे चीन ने प्रगति की उड़ान और वैश्विक बाजार में वर्चस्व इसी आबादी के बूते पाया है। इसलिए चीन को अब यह चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत इस आबादी के बूते अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सफल न हो जाए? क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 68 प्रतिशत आबादी ऐसे क्रियाशील लोगों की या युवाओं की है, जो उत्पादकता से निरंतर जुड़े रहकर अपने उत्पादों को दुनिया के बाजार में पहुंचाकर अर्थव्यवस्था को शिखर पर पहुंचा सकते हैं।

भारत की आबादी चीन से अधिक बढ़ गई है, तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि यह संभावना बहुत पहले से जताई जा रही थी कि भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा।

वर्तमान में दुनिया की आबादी 8 अरब

की संख्या पहले ही पार कर चुकी है। भारतीय आबादी के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक पांचवे व्यक्ति में से एक भारतीय है। क्योंकि भारत 142.86 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। चीन की आबादी इस समय 142.57 करोड़ है। हमारी आबादी उससे 29 लाख अधिक है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश को जहां यह बड़ी चुनौती है, वहीं उसे वरदान बनाने की जरूरत है। हालांकि जागरूकता और परिवार नियोजन के उपायों के चलते दुनिया में जन्मदर घटी है। हालांकि भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है, जिसने आबादी पर नियंत्रण के लिए 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया था।बावजूद जनसंख्या वृद्धि होती रही है। जनसांख्यिकीय विश्लेषण के निष्कर्ष

बताता है कि 1950 के बाद वर्तमान में जन्मदर सबसे कम है। अतएव यहां सवाल उठता है कि फिर आबादी का घनत्व क्यों बढ़ रहा है? दरअसल चिकित्सा सुविधाओं और एक वर्ग विषेश की माली हैसियत बढ़ने से औसत उम्र बड़ी है। इस दायरे में आने वाले लोग उत्पादकता से जुड़े नहीं रहने के बावजूद उच्च श्रेणी का जीवन जी रहे हैं। नतीजतन यह आबादी जापान, चीन और दक्षिण कोरिया की तरह भारत के युवाओं को रोजगार में बाधा बन रही है। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी 15 से 36 आयु वर्ग के युवाओं में है। यदि हम पीपुल्स कमीशन की रिपोर्ट का उल्लेख करें तो 15 से 29 आयु समूह में बेरोजगारों की संख्या 27.8 करोड़ है। हालांकि इसमें अनेक बेरोजगार ऐसे हैं, जिनके पास काम तो है, लेकिन आमदनी का अनुपात सन्तोषजनक नहीं है। भारत के सीमांत राज्यों में विदेशियों की घुसपैठ और कमजोर जाति समूहों का धर्मांतरण भी आबादी का घनत्व बढ़ाने और बिगाड़ते हुए रोजगार के संकट के साथ स्थानीय मूल निवासियों से टकराव के हालात उत्पन्न कर

रहा है। इसीलिए जनसंख्या नीति में समानता की बात की जा रही है।

अब जबकि हम आबादी में चीन से आगे हैं, तब हमें चीन से यह सबक लेने की जरूरत है कि उसने अपने मानव संसाधन को किस तरह से श्रम और उत्पादकता से जोड़ा और दुनिया के बाजारों को अपने उत्पादों से पाट दिया। क्योंकि चीन में बड़ी आबादी के बावजूद रोजगार का संकट भारत की तरह नहीं गहराया। जाहिर है, चीन की उन्नति और उत्पदकता में इसी आबादी का रचनात्मक योगदान रहा है। सस्ते कुशल एवं अर्द्धकुशल लोगों से उत्पादन कराकर चीन ने अपना माल दुनिया के बाजारों में भर दिया है। जबकि भारत बड़ी कंपनियों को सब्सिडी देने के बावजूद स्वदेशी उत्पादन में आबादी के अनुपात में उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर पाया। मेक इन इंडिया के नाम पर हाल ही में दो कंपनियों हीरो इलेक्ट्रिक और ओकीनावा की 370 करोड़ रुपए की सब्सिडी की राशि देने पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने फास्टर एडॉप्सन एंड मैन्यू फैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम)-2 योजना के तहत दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने हेतु 10,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन को सब्सिडी दी जाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 15000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। लेकिन यह सस्सिडी तभी दी जाएगी, जब उत्पादन स्वदेशी के स्तर पर किया जाए। लेकिन सरकार ने जब जांच की तो पाया कि इन कंपनियों ने इन वाहनों में चीन से आयात कल-पुर्जे इस्तेमाल किए हैं। इसी कारण दो पहिया वाहनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस धोखाधड़ी के चलते हीरो इलेक्ट्रिक की 220 करोड़ और ओकीनावा की 150 करोड़ रुपए की सब्सिडी रोक दी। इन धोखाधड़ियों के चलते भी भारत स्वदेशीकरण के साथ बेरोजगारी से पार नहीं पा रहा है।

यदि हम चीन में ज्ञान-परंपरा से दीक्षित लोगों को रोजगार देने की बात करें तो वहां सरकार या कंपनी द्वारा गांव-गांव कच्चा माल पहुंचाया जाता है। जब वस्तु का निर्माण हो जाता है, तो उस माल को लाने और मौके पर ही भुगतान करने की जबावदेही संस्थागत है। इसका फायदा यह

होता है कि ग्रामीण अपने घर में ही वस्तु का उत्पादन कर लेता है। नतीजतन वस्तु की लागत न्यूनतम होती है। यदि यही व्यक्ति शहर में जाकर उत्पादकता से जुड़े तो उसे कमाई की बड़ी राशि रहने, खाने-पीने और यातायात में खर्च करनी पड़ जाती है। भारत में उत्पादन के छोटे-बड़े कारखाने शहरों में हैं। लिहाजा वस्तु की लागत अधिक आती है। चीन में होली, दिवाली और रक्षाबंधन से जुड़ी जो वस्तुएं आयात होती हैं, उनका उत्पादन चीन के गांव में ही होता है। जाहिर है, यदि बड़ी जनसंख्या उत्पादन से जुड़ जाए बेरोजगारी की समस्या से एक हद तक छुटकारा मिल सकता है। युवा समस्या तब बनते हैं, जब उनके हाथों में काम न हो ? जापान और दक्षिण कोरिया में जनसंख्या का घनत्व भारत से ज्यादा है, बावजूद ये देश हमसे अधिक संमृद्ध होने के साथ स्वदेशी प्रौद्योगिकी से उत्पादन और उसके निर्यात में हमसे आगे हैं। अतएव भारत को चीन, जापान और कोरिया से सीख लेने की जरूरत है।

यह बात लोगों को रोजगार से जोड़ने की हुई, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर एक नीति बने बिना, बात बनने वाली नहीं है। दो बच्चों की यह नीति सभी धर्म एवं समुदायों के लोगों पर समान रूप से लागू हो। क्योंकि जनसंख्या एक समस्या भी है और एक साधन भी है। लेकिन जिस तरह से देश के सीमांत प्रांतों और कश्मीर में जनसंख्यात्मक घनत्व बिगड़ रहा है, उस संदर्भ में जरूरी हो जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द वजूद में आए। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ हिंदुओं की आबादी घटने पर कई बार चिंता जता चुका है। साथ ही हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह भी संघ के कार्यवाहक देते रहे हैं। इन बयानों को अब तक हिंदु पक्षधरता के दायरे में समेटने की संर्कीण मानसिकता जताई जाती है, जबकि इसे व्यापक दायरे में लेने की जरूरत है। कश्मीर, केरल समेत अन्य सीमांत प्रदेशों में बिगड़ते जनसंख्यात्मक अनुपात के दुष्परिणाम कुछ समय से प्रत्यक्ष रूप में देखने में आ रहें हैं। कश्मीर में पुश्तैनी धरती से 5 लाख विस्थापित हिंदुओं का पुर्नवास धारा-370 हटने के बाद भी आतंकी घटनाओं के चलते नहीं हो पाया है। बांग्लादेसही धुसपैठियों के चलते असम व अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बदलते जनसंख्यात्मक घनत्व के कारण जब चाहे तब दंगों के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। यही हालात पश्चिम बंगाल में देखने में आ रहे हैं। जबरिया धर्मांतरण पूर्वोत्तर और केरल राज्यों में बढ़ता ईसाई वर्चस्व ऐसी बड़ी वजह बन रही हैं, जो देश के मौजूदा मानचित्र की शक्ल बदल सकती हैं ? हालांकि चंद तथाकथित बौद्धिक जनसंख्या नियंत्रण के नीतिगत उपायों में बड़ी बाधा हैं और ये तर्क से ज्यादा कहीं कुतर्क करते हैं।लिहाजा परिवार नियोजन के एकांगी उपायों को खारिज करते हुए आबादी नियंत्रण के उचित उपायों पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है।

पानी पर कब्जे का सवाल

शब्बीर कादरी

पिछले कुछ वर्षो से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गिद्ध दृष्टि पानी यानि नीला सोना पर आकर अटक गई है। जाहिर है वे जानती है कि आने वाले दिनों में इसका महत्व जमीन के नीचे से निकलने वाले कच्चे तेल से भी ज्यादा होगा, इसलिए विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और उनके अधीन काम करने वाली अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संस्थाओं ने सुनियोजित योजना के तहत पानी को इक्कीसवी सदी का सबसे बड़ा एजेंडा घोषित किया है। वे बता रहे हैं कि पानी का निजीकरण कर उसका नियोजित उपयोग जीवन के लिए कितना जरूरी है और इस जटिल, गंभीर और अत्यावश्यक काम को दुनिया की चंद बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही सफलतापूर्वक कैसे प्रतिपादित कर सकती हैं। बार-बार लिखा जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध तेल के लिए नहीं पानी के लिए होगा। विश्व बैंक के आँकड़े चेता रहे हैं कि दुनिया की आबादी का छटवाँ हिस्सा पानी अर्थात् एक अरब से अधिक लोग जलसंकट से त्रस्त क्षेत्र में जीने को मजबूर होंगे। यदि समय रहते उनके लिए समुचित पानी का प्रबंध नहीं किया गया तो वर्ष 2025 तक परिस्थिति विस्फोटक रूप धारण कर सकती है। पानी से जूझ रही यह आबादी भारत, पाकिस्तान और चीन की है, जो आने वाले कल की तबाही से बेखौफ, लगभग बेफिक्र हो सत्ता के खेल में मदमस्त है।

ज्ञात हो कि वर्तमान में कच्चे तेल की जगह अब पानी का कारोबार तेजी से विश्व व्यापी रूप धारण करता जा रहा है। वर्ष 1994 से लेकर 1988 के बीच इस क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के एक दूसरे में विलय और अधिग्रहण को करीब 140 घटनाएँ हुई हैं। इस विलय और अधिग्रहण का बाजार मूल्य कुल करीब 10 अरब पौंड आंका गया है। आज जो कंपनी नम्बर एक है वहीं कल दूसरे, तीसरे, पांच या दस मुकाम पर पहुँच सकती हैं। इसी आधार पर अभी यह कहना मुश्किल है कि इस समय दुनिया में पानी का सबसे बड़ा सौदागर कौन है। यह जरूर है कि इस धंधे में लिप्त टॉपटेन कंपनियों में एनरॉन नाम की कुख्यात संस्था भी शामिल है, जिसने डाभोल परियोजना के नाम से महाराष्ट्र में तहलका तो मचाया ही, यहाँ की अर्थव्यवस्था की कमर भी तोड़ डाली थी। वैसे फिलहाल पानी क्षेत्र की सबसे बड़ी फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी विवेन्डी है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी सुएज लियोन्नेलज है। यह कंपनी भी फ्रांस की है। फिलहाल विश्व का 70 प्रतिशत निजी पानी बाजार इन्हीं दो कंपनियों के कब्जे में है। सूएज का दुनिया भर के 120 देशों में कारोबार है तो विवेन्डी का 90 देशों में और दोनों का कुल सालाना बाजार 70 अरब डालर से ज्यादा है। इस फ्रांसीसी कंपनी का कारोबार 80 देशों में फैला है। पानी क्षेत्र को तीसरी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी बायगीज है। ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कम्पनी यूनाइटेड यूटिलिटी पानी क्षेत्र की चौथी बड़ी कम्पनी है और अब अमेरिका की एनरॉन कम्पनी ने भी पानी के क्षेत्र में पैर पसारे हैं जो पचास देशों तक फैले हैं। इसके बाद जर्मन कम्पनी आर.डब्ल्यू.ई. का भी नाम आता है,

जिसका कुल व्यापार इसी क्षेत्र में 50 अरब डॉलर प्रतिवर्ष तक पहुँच चुका है। इसके अलावा शीतपेय पिलाने वाली पेप्सी, कोक और नेस्ले आदि कम्पनियाँ भी पानी के बाजार में कूद चुकी हैं। एशिया, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, मध्यपूर्व और दक्षिण अमेरिका के करीब दो करोड़ से अधिक लोगों तक सेवर्न ट्रेन्ट नाम की एक और संस्था पाँच महाद्वीपों के लगभग 80 लाख लोगों तक अपने पानी का जायका पहुंचा चुकी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि पानी को इन दस बड़ी कंपनियों ने अभी तक पचास करोड़ लोगों तक अपना-अपना पानी पहुंचाया है। और प्रगति की यही रफ्तार रही तो आने वाले दो-तीन वर्षो में हीं इनकी पहुँच 100 करोड़ लोगों तक आसानी से हो जाएगी, जबकि तरह पानी के विश्व व्यापार में इनकी हिस्सेदारी 500 अरब डॉलर हो जायेगी।

तेजी से अपनी प्रगति का ग्राफ चूमती इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अब भारत के लिए भी पानी का एजेंडा तैयार किया है अर्थात् हमारे घरों, खेतों, खलिहानों और कारखानों में विदेशी कम्पनियाँ पानी की व्यवस्था करेंगी। विश्व बैंक की रिपोर्टस् में भारत को बढ़ती जनसंख्या नगरीकरण और औद्योगिकीकरण को तेज प्रक्रिया और घटते जल संसाधनों की भयावह तस्वीर पेश की गई है। इन रिपोटों में कहा गया है कि यदि भारत निरंतर आर्थिक विकास को आकांक्षा रखता है और सामाजिक तथा पर्यावरणीय स्थिति में सुधार करना चाहता है तो उसे जल प्रबंधन में बुनियादी बदलाव लाना होगा। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में ग्राउंड वाटर का प्रबंधन बहुत कमजोर है जिसके चलते बिजली की आपूर्ति ठीक तरह से नहीं हो पाती, परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्राउंड वाटर को स्थिति से निपटने के लिये रिपोर्ट नए कानून बनाने को सिफारिश भी करती हैं। विश्व बैंक ने जिन सिफारिशों को इन रिपोर्टस् के माध्यम से लागू किए जाने की वकालत की है उसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर में न हैंडपम्प लगवा सकता है, न कुओं का निर्माण कर सकता है और न कोई तालाब खुदवा सकता है ऐसा इसलिये कि जलप्रबंधन से संबंधित यह नया कानून ग्राउंड वाटर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार स्थापित करने वाला होगा और आम आदमी पानी के लिए तरस और तड़प उठेगा। यह ठीक वैसा हो होगा जैसा कि अरब देशों में किसी व्यक्ति के घर के अंदर की जमीन से निकलने वाले तेल पर उस व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। यदि विश्व बैंक की इन रिपोर्टस को सरकार द्वारा मान्य कर लिया जाता है तो निश्चित जानिये कि हमारे देश के लोगों को बूंद-बूंद पानी के

लिये विदेशी कम्पनियों से भीख मांगनी होगी, क्योंकि इन्हीं कम्पनियों से लायसेंस प्राप्त कर ही आप हैंडपम्प लगा सकते हैं, कुआं खोद सकते हैं, ट्यूबवेल लगा सकते हैं। अब यदि आपके पास पैसा है तो लीजिये पानी वरना, मरिये प्यासे।

विश्व बैंक को पानी के निजीकरण की इन्हीं सिफारिशों ने पानी की चिंता करने वालों की नींद उड़ा रखी है। हर एक मंच से इसके विरोध में स्वर सुनाई देने लगे हैं, पर पानी के निजीकरण के समर्थन में भी कुछ लोगों के जाइज तर्क हैं। ऐसे समर्थकों का मत है कि हम अपने देश में प्रतिवर्ष 380 अरब घनमीटर भूमि से पानी निकालते हैं, जिसका 93 प्रतिशत कृषि में चार प्रतिशत उद्योग में तथा तीन प्रतिशत घरेलू उपयोग वाले जल का 80-90 प्रतिशत भूमिगत जल होता है, जबकि कृषि और उद्योग में आधा-आधा हम भूमिगत और सतह के जल का उपयोग करते हैं। सिर्फ कृषि के लिये हमारे यहाँ एक करोड़ सत्तर लाख पम्पिंग सेटों का उपयोग होता है, लेकिन यह पूरा जल या तो मुफ्त है या इस पर भारी सरकारी अनुदान मिलता है। इसके विपरीत कुछ इलाकों में अब पानी मिलना बंद हो गया है। उदाहरण के लिए सौराष्ट्र में जहाँ 100 फुट की गहराई पर पानी मिल जाया करता था अब 1800 फुट नीचे भी मुश्किल से पानी मिलता है। यही स्थिति भारत के अन्य राज्यों को भी है। सच यह है कि अभी तक हम पानी के प्रति गंभीर नहीं। उसे हमने कभी खत्म न होने वाला मुफ्त का माल समझ रखा है। विश्व बैंक का सुझाव स्वागत योग्य है कि पानी कहाँ से लिया जाए, कैसे लिया जाए। इस पर भी विभिन्न देशों की सरकारों को स्पष्ट नीति बनानी होगी। उसने सुझाव दिया है कि पानी का महत्व समझ में आए और वे अनावश्यक पानी बर्बाद न करें। सदैव से ही विदेशी कम्पनियों ने किसी भी दूसरे देश में परोपकार के लिए अपने पैर नहीं फँसाए, केवल पैसा बनाने, मुनाफा कमाने के लिए वे नए-नए षड्यंत्र रचते रहते हैं। अफसोस यह है कि कुर्सी के खेल में मस्त, बोतलबंद पानी पीने वाले हमारे राजनेता देश में उपलब्ध पानी के कुशल प्रबंधन में भी बार-बार फेल हुए हैं। यदि ईमानदारी से ही पानी का प्रबंधन कर दिया गया तो हमें विदेशी योजना को लागू करने की न तो जरूरत पड़ेगी और न प्यासे मरने की नौबत आएगी। इस सम्पदा के नियोजित वितरण, दोहन और कुशल प्रबंधन के द्वारा हम भविष्य को संभावित गंभीर समस्या से सरलतापूर्वक निपट सकते हैं और इसके लिए हम सरकार से सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं।

Hunger and Food Distribution in India

Gatik Dewani

In India, distribution of food and hunger are major problems. India's economy is among the fastest-growing in the world, but it still has a long way to go before it can be considered food secure. India has the most hungry people in the world, with over 195 million people suffering from hunger, according to a report by the United Nations World Food Programme (WFP). The causes of hunger in India, the food distribution system, and the solutions that can be implemented will all be covered in this article.

Poverty is one of the main factors contributing to hunger in India. In India, nearly 270 million people live in poverty, and many of them have trouble paying for rudimentary necessities like food. The high rate of poverty in India is made worse by problems like underemployment, unemployment, and illiteracy, which make it challenging for many people to make a living wage.

The unequal distribution of wealth is another factor causing hunger in India. While the majority of the population struggles to make

ends meet, a small number of people and corporations control a sizable portion of the nation's wealth. As a result, many people are now in a position where they are unable to afford to purchase enough food to meet their basic needs.

India faces a significant hunger problem, and there must be coordinated efforts to address and reduce it. In order to do this, the government should improve the food distribution system, address issues of poverty and income inequality, and encourage nutrition education. By taking these steps, it will be possible to end hunger and guarantee that everyone in India has access to enough food.

Another important factor contributing to hunger in India is the food distribution system. Agricultural production in the nation is extremely inefficient, and many farmers struggle to feed their families. Additionally, many people who require food assistance are unable to access it due to the government's food distribution programmes being frequently marred by corruption and poor management.

In order to combat hunger and malnutrition in the nation, the Indian government administers a

The Hunger Index, also known as the Global Hunger Index (GHI), is a tool used to measure hunger and malnutrition levels in countries around the world. The index takes into account several indicators, such as undernourishment, child wasting, child stunting, and child mortality, to give a score ranging from 0 to 100, with a higher score indicating a higher level of hunger.

India has been included in the Global Hunger Index since its inception in 2006. In the latest report released in 2021, India ranks 101 out of 116 countries, with a score of 30.9. This places India in the "serious" hunger category, with high levels of hunger and malnutrition.

The report highlights several challenges that India faces in addressing hunger and malnutrition, including poverty, inequality, low levels of education, and poor access to healthcare. The report also notes that the COVID-19 pandemic has exacerbated the already existing food insecurity and malnutrition issues in India.

Despite these challenges, India has made some progress in reducing hunger and malnutrition levels in recent years. According to the report, India's GHI score has decreased from 38.9 in 2000 to 30.9 in 2021, indicating an improvement in the country's hunger and malnutrition situation.

number of food distribution programmes. These initiatives consist of the Integrated Child Development Services (ICDS), the Mid-Day Meal Scheme (MDMS), and the Public Distribution System (PDS) (ICDS).

The PDS, India's biggest food distribution programme, offers subsidised food grains to millions of people all over the nation. In accordance with this programme, qualified families receive ration cards that they can use to buy food grains from government-run ration shops at a discounted price. Other necessities like sugar, kerosene, and cooking oil are also offered at discounted prices through the PDS.

Another important food distribution programme in India is the MDMS, which offers free meals to schoolchildren to combat malnutrition and promote attendance. Every student who participates in the

programme is given a free lunch every midday in all public and government-aided schools across the nation.

The ICDS is a programme designed to give pregnant women, nursing mothers, and children under the age of six extra nutrition. The programme offers a variety of services, such as vaccinations, health checkups, and supplemental nutrition.

Despite the government's efforts to combat hunger and malnutrition through these initiatives, India's food distribution system has a number of problems. Corrupt officials steal money and divert food grains intended for distribution to the open market, which is one of the main problems. Furthermore, a lot of ration shops are poorly run, with lengthy wait times and subpar food supplies.

There are a number of actions that can be taken to address the issues of hunger and food distribution in India. Addressing the nation's poverty and income inequality is one of the most important steps. This can be achieved by expanding employment opportunities, enhancing access to healthcare and education, and enacting wealth redistribution laws.

Enhancing the agricultural sector's effectiveness is a crucial next step. This can be accomplished by funding cutting-edge agricultural technology and giving farmers access to credit, knowledge, and markets. The government should also make sure that farmers are protected from price volatility and that they receive fair prices for their crops. Additionally, the government must address the problems with corruption and poor management in the food distribution system.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.